जनता के गोठ

Website- https://www.jantakegoth.com

● वर्ष -01 ● अंक- 297 ● रायपुर, गुरुवार 15 अक्टूबर 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ- 12 ● मूल्य- 2 रुपया ● संपादक- शुभम वर्मा ● PRGI Reg No : CTBIL/25/A1787

पहला कॉलम

गर्भवती महिला पत्रकार ने राहुल गांधी पर लगाया धक्का देने का आरोप, कांग्रेस ने नकारा

नई दिल्ली। चुनाव आयोग की नीतियों के विरोध में सोमवार को विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की ओर से उच्चतम न्यायालय परिसर में निकाले गए मार्च के दौरान विवाद खड़ा हो गया। समाचार वेबसाइट 'वनइंडिया' की महिला पत्रकार ऋचा पाराशर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। पाराशर के अनुसार, वह तीन महीने की गर्भवती हैं और घटना में चोटिल होने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार करा रही हैं। वहीं, कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश बताया है। अस्पताल में उपचाराधीन ऋचा पाराशर ने आरोप लगाया कि वह राहुल गांधी से बयान लेने की कोशिश कर रही थीं, तभी उन्होंने कथित तौर पर उनका हाथ आक्रामक तरीके से पकड़कर खींचा। पत्रकार के अनुसार, राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने भी उन्हें और उनके छायाकार को धक्का दिया, जिससे वह सीढ़ियों पर गिर गईं।

दिल्ली में प्रतिबंध के कारण 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान, व्यापारी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के कारण लगाए गए प्रतिबंधों और उनसे कारोबार पर पड़ रहे असर को लेकर वकीलों तथा व्यापारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रतिबंधों के कारण व्यापारियों को करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने निर्धारित प्रदर्शन स्थलों पर मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने की मांग की है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इन याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने अदालत में कहा कि उनकी मांग केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले से निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के कार्यान्वयन तक सीमित है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अपने मौलिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं।

भारतीय रेल की माल ढुलाई में 6.14 प्रतिशत की वृद्धि, सितंबर में 13.53 करोड़ टन माल का परिवहन

नई दिल्ली। भारतीय रेल ने सितंबर 2026 में माल ढुलाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। सितंबर 2025 की तुलना में इस वर्ष सितंबर में माल ढुलाई 6.14 प्रतिशत बढ़कर 13.535 करोड़ टन हो गई। पिछले वर्ष इसी महीने में 12.752 करोड़ टन माल की ढुलाई की गई थी। खाद्यान्न, सीमेंट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले क्लिंकर, घरेलू माल डिब्बों और कोयले सहित कई प्रमुख वस्तुओं की ढुलाई में वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रेल के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान भी माल ढुलाई में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। इस अवधि में कुल 83.37 करोड़ टन माल की ढुलाई की गई।

मोदी कैबिनेट के तीन बड़े फैसले

रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस,दिव्यांगों को अब जन्म से पेंशन....

नई दिल्ली। एजेंसी



केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों, दिव्यांगों और देश के वित्तीय क्षेत्र को लेकर तीन बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पांच साल तक जारी रखने और दिव्यांग पेंशन के पात्रता नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। वहीं, आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन से जुड़े फैसले को भी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। इस पर लगभग 2,009 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारी त्योहारों के दौरान भी पटरियों, वर्कशॉप और यात्रियों की सेवा में लगातार काम करते हैं। यह बोनस उनके योगदान और मेहनत को सम्मान देने का प्रयास है। मंत्री ने यह भी बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। करीब 1.65 लाख रिक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए पांच वर्षों में कुल 53,428 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। सरकार के मुताबिक, देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत सहायता राशि में बदलाव किया गया है। 0 से 79 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए 625 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम आयु की शर्त समाप्त करने का फैसला किया गया है। अब पात्रता के अन्य निर्धारित मानदंड पूरे करने वाले व्यक्ति जन्म से ही योजना के दायरे में आ सकेंगे। दिव्यांगता के लिए बेंचमार्क मानदंड को भी मौजूदा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने योजना और उसकी उप-योजनाओं के नाम बदलने को भी मंजूरी दी है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना पहले की तरह जारी रहेंगी। नए नियमों को लागू करने के लिए दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन से जुड़े फैसले को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य देश के वित्तीय सेवा क्षेत्र में नई पूंजी लाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

आईएएस एस.जयवर्धन गृह मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त तीन सप्ताह के भीतर संभालना होगा पदभार



केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 2014 बैच के आईएएस अधिकारी एस. जयवर्धन को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय गृह मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। भारत सरकार ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार को सूचना भेजते हुए अधिकारी को जल्द कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को ई-मेल के माध्यम से नियुक्ति संबंधी निर्देश भेजे गए हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आईएएस एस. जयवर्धन को उनके वर्तमान दायित्वों से तत्काल मुक्त किया जाए, ताकि वे नई दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय में उप सचिव के पद पर अपना नया कार्यभार संभाल सकें। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत हुई इस नियुक्ति में पदभार ग्रहण करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। निर्देशों के अनुसार, अधिकारी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 'की दयनीय हालत...

जजों को आईपीसी की धारा 304 पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पता है.....

नई दिल्ली/ एजेंसी



छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट' के जजों को आईपीसी की धारा 304 पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पता' है। ये खुद देश के शीर्ष न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसे लेकर शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 'छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट' पर गंभीर और कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली की हालत को दयनीय बताते हुए कहा कि जजों को यह तक नहीं पता कि आईपीसी की धारा 304 (1) और (2) क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में ये कड़ी टिप्पणी की है। साथ ही मामले में याचिकाकर्ता और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने हत्या के एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि जरा हाई कोर्ट की दयनीय हालत तो देखिए। जजों को यह तक नहीं पता कि आईपीसी की धारा 304 पार्ट वन और 304 पार्ट टू क्या है और आप उम्मीद करते हैं कि जज सबूतों को समझेंगे? दरअसल याचिकाकर्ता पर सरायपाली की अतिरिक्त सत्र न्यायालय (स्छ कोर्ट) में आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील की थी। हालांकि यहां हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी लापरवाही कर दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी लापरवाही से और कानून की समझ के बिना अपील को आंशिक रूप से मंजूर कर लिया। इतना ही नहीं सजा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) से बदलकर आईपीसी की धारा 304 पार्ट टू (गैर-इरादतन हत्या) कर दिया।

प्राथमिक जांच में आरोप प्रमाणित

पीड़िता की आपत्ति पर जांच टीम में महिला आईपीएस अधिकारी नियुक्त किया

बिलासपुर। राजकिशोरनगर, बिलासपुर निवासी एक महिला योगा टीचर को तत्कालीन आईजी पुलिस रतनलाल डांगी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले में अब एक महिला आईपीएसअफसर पारूल माथुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि, पीड़िता ने आईजी पुलिस रतनलाल डांगी पर अश्लील फेटो एवं मैसेज भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता द्वारा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के समक्ष गंभीर शिकायत किए जाने पर डीजीपी द्वारा आईपीएस आनंद छाबड़ा एवं आईपीएस मिलना कुर्रे को प्रारंभिक जॉचकर्ता अधिकारी नियुक्त कर उक्त गंभीर मामले की जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परंतु उक्त जॉच कार्यवाही में पक्षपात एवं गड़बड़ी किए जाने पर पीड़िता ने हाईकोर्ट के वकील अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, उक्त प्रारंभिक जॉच कार्यवाही में आईपीएस आनंद छाबड़ा एवं मिलना कुर्रे द्वारा पक्षपात एवं जॉच कार्यवाही में अनियमितता कर निलंबित आईपीएस रतनलाल डांगी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अत: पीड़िता द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए जॉच अधिकारियों को बदलने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त मामले को अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील मानते हुए सचिव (गृह विभाग) एवं पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को उक्त मामले में तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।



प्रशांत अग्रवाल की जगह पारूल माथुर को जिम्मा

पीड़िता की आपत्ति पर सचिव, गृह विभाग द्वारा दिनांक 29.09.2026 को संज्ञान लेते हुए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी प्रशांत अग्रवाल को हटाकर महिला आईपीएस अधिकारी पारूल माथुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर उक्त दोनो आईपीएस अधिकारियों को जॉच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, उच्च न्यायालय द्वारा सचिव, गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट होकर याचिका का अंतिम निराकरण कर दिया गया।

उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला और तंबाकू युक्त खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध

देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिनयुक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किया। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है।

ममता का सौदा

1.80 लाख रूपए के लालच में अपने ही बच्चे को बेचा,पश्चिम बंगाल से पुलिस ने किया बरामद....

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. पैसों के लालच में कलयुगी मां ने अपने ही छोटे बच्चे को बेच दिया. 1 लाख 80 हजार रुपये में उसका सौदा कर लिया. पश्चिम बंगाल से पुलिस ने 9 से 10 माह के बच्चे को सकुशल बरामद किया है. मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों की भूमिका भी सामने आई है. घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र की है. पुलिस जांच के मुताबिक, मामला मार्च 2026



का बताया जा रहा है. आरोप है कि बच्चे की खरीद-फरोख्त ?1.80 लाख में की गई थी. मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान बच्चे को बेचने के मामले में उसकी मां समेत अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आई. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामले की जांच के दौरान पुलिस को पश्चिम बंगाल में बच्चे के होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को वहां से सकुशल बरामद किया. पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित संरक्षण में ले लिया है. मामले में पश्चिम बंगाल निवासी दो आरोपियों की भूमिका भी उजागर हुई है. पुलिस अब इस पूरे प्रकरण से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है. कुनकुरी पुलिस ने बच्चे की खरीद-फरोख्त के आरोप में किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है.



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के अवसर पर बरेली जिले में एक ग्राम प्रहरी को सम्मानित किया।

कोर्ट का बड़ा फैसला,नीला ड्रम हत्याकांड

मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा..

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में आज, 14 अक्टूबर 2026 को जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 13 महीने तक चली बहस, 127 तारीखें और 22 से अधिक गवाहों के बयान के बाद आज कोर्ट ने फैसले का ऐलान किया। जिला कोर्ट ने दोनों आरोपियों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को अदालत पहले ही दोषी करार दे चुकी थी। अब दोनों के लिए अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। सजा सुनाए जाने से पहले बुधवार सुबह अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों दोषियों से सवाल किए। जज ने उनसे पूछा कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं। इस पर दोनों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

जंतर-मंतर प्रदर्शन केस

आशुतोष रांका और सौरव दास को पांच दिन की न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली/ एजेंसी

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों नेताओं को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया था। अदालत के आदेश के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की प्रक्रिया की गई। पार्टी नेताओं के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान वे तिरंगा लेकर पहुंचे थे और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए थे। वहीं, पुलिस की कार्रवाई को लेकर सीजेपी ने सवाल उठाए हैं और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया है। जानकारी के मुताबिक, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) अदालत ने पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। दोनों पर पहले से तय बेल बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है। इसी मामले में शामिल तीसरे सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे को नया बेल बॉन्ड भरने के बाद राहत मिली। सीजेपी के वकील अभिष्ट हेले ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि नेताओं को इस आशंका के आधार पर हिरासत में भेजा गया कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। वकील ने यह भी दावा किया कि नेताओं ने आम लोगों को



मौके पर जुटने के लिए कोई अपील नहीं की थी और न ही बेल बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया था। जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद सीजेपी नेताओं ने वहीं प्रदर्शन करने का फैसला किया। रांका, दास और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार कर अंदर पहुंचे और तिरंगा लहराते हुए नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे नेताओं की तस्वीर साझा करते हुए पूछा कि क्या अब राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी गैरकानूनी हो गया है। उन्होंने कहा कि नेताओं को जेल भेजने से पार्टी का विरोध कमजोर नहीं होगा। सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे ने आरोप लगाया कि तिरंगा लहराने और 'भारत माता की जय' के नारे लगाने के कारण आशुतोष रांका और सौरव दास को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

राजपुर जनपद में योजनाओं की समीक्षा, सीईओ ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

आवास निर्माण में तेजी लाने और लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने पर जोर

बलरामपुर (जनता के गोठ) : जनपद पंचायत राजपुर में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय कुमार दुबे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वीबी-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

आवास योजनाओं में तेजी लाने पर जोर

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम जनमन आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। अप्रारंभ आवासों का निर्माण जल्द शुरू कराने तथा अधूरे आवासों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। निरस्त जनमन आवासों की राशि वापसी, भूमि विवाद से जुड़े आवासों के प्रस्ताव और पहाड़ी कोरवा हितग्राहियों के नवीन जनमन सर्वे के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाने पर भी चर्चा हुई।

इसके अलावा पीएम जनमन योजना के तहत डीबीटी, आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों के मामलों में नियमानुसार आरआरसी कार्रवाई के लिए पंचनामा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

मनरेगा और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों की समीक्षा

वीबी-जी राम जी के अंतर्गत श्रमिकों की उपस्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही ब्लॉक, सड़क किनारे और स्कूल परिसरों में वृक्षारोपण के कार्यों को आगे बढ़ाने तथा जल संरक्षण के लिए बोल्डर चेक, कंटूर ट्रेंच और गली प्लग जैसे कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

स्वच्छता से लेकर पेंशन योजनाओं तक हुई चर्चा



स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों, सोख्ता गड्ढों और बालिका शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही पीएम सूर्यघर योजना, पेंशन हितग्राहियों के केवाईसी सत्यापन, आंगनबाड़ी एवं आदि आदर्श योजना के निर्माण कार्यों और पुराने निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्रों की स्थिति पर चर्चा हुई।

बैठक में करदाताओं की जानकारी संकलित करने तथा 'हमर सुघर छत्तीसगढ़' बेसलाइन सर्वे की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय कुमार दुबे ने तकनीकी अमले और ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने लंबित कार्यों की प्रगति पर ध्यान देने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मनरेगा सहित विभिन्न शाखाओं के प्रभारी, तकनीकी सहायक, एडीईओ, पीओ, बीसी, एसडीओ, करारोपण अधिकारी, बीपीएम और एनआरएलएम के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सुपर गर्ल्स' में बोरपदर की बेटियों का परचम, कविता पाठ और वाद-विवाद में प्रथम स्थान

जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आराध्या नेताम और खुशी बघेल ने दिखाया हुनर, विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल

बकावंड जनता के गोठ।- जगदलपुर के कुम्हारवंड स्थित गुण्डाधुर कृषि महाविद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय 'सुपर गर्ल्स' प्रतियोगिता में प्राथमिक शाला साहूकारपारा, बोरपदर की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और विकासखंड बकावंड का नाम रोशन किया। छात्राओं ने कविता पाठ और वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में कविता पाठ विधा में आराध्या नेताम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में खुशी बघेल ने तृतीय स्थान हासिल किया। वाद-विवाद प्रतियोगिता में पक्ष की ओर से प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत करते हुए आराध्या नेताम प्रथम रहीं, जबकि विपक्ष में अपने विचारों को मजबूती से रखते हुए खुशी बघेल ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राओं की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार और क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।



कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधान अध्यापक बेणुधर जोशी तथा संकुल समन्वयक गंगाराम बघेल को भी सम्मानित किया गया। छात्राओं की सफलता को उनकी मेहनत, लगन, आत्मविश्वास और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम माना जा रहा है।

इस उपलब्धि पर विकासखंड बकावंड के खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर यादव, खंड स्त्रोत समन्वयक सोनसिंह बघेल, संकुल समन्वयक गंगाराम बघेल, संस्था प्रमुख बेणुधर जोशी, सहायक शिक्षक डोमेंद्र कुमार गंगबेर, शाला प्रबंधन समिति, पालकों एवं विद्यालय परिवार ने छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम में सहायक कलेक्टर यशवंत नायक, जिला शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल, जिला स्त्रोत समन्वयक अशोक पांडे सहित विभिन्न विकासखंडों के खंड शिक्षा अधिकारी, खंड स्त्रोत समन्वयक, चयनित शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

बोरपदर की छात्राओं की यह सफलता ग्रामीण अंचल की प्रतिभा और बालिकाओं के बढ़ते आत्मविश्वास का उदाहरण है। उनकी उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी है।

बिच्छू गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, आरोपी पर्यटकों को डरा-धमका कर करते थे

धारदार हथियार दिखाकर डराने और वसूली करने का आरोप, आरोपियों से तीन हथियार जब्त

कवर्धा। कबीरधाम जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल सरोधा बांध में पर्यटकों को डराने-धमकाने और धारदार हथियार लहराने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कथित तौर पर समूह बनाकर खुद को 'बिच्छू गैंग' बताते थे। पुलिस के अनुसार, समूह के कुछ सदस्य पर्यटकों को हथियार दिखाकर भयभीत करने और उनसे पैसे वसूलने जैसी गतिविधियों में संलिप्त थे। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया,



जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, सरोधा बांध के पास धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने की सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में मौके से तीन युवकों को पकड़ा। उनके कब्जे से एक-एक धारदार लोहे का हथियार जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शंकर धुर्वे (30 वर्ष), निवासी ग्राम छांटा, थाना पिपरिया; अशोक मरकाम (21 वर्ष), निवासी ग्राम मन्नाबेदी, थाना भोरमदेव; और देवकुमार पटेल उर्फ गब्बर (18 वर्ष), निवासी ग्राम रौचन, थाना भोरमदेव के रूप में हुई है। पुलिस ने शंकर धुर्वे और देवकुमार पटेल के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 तथा अशोक मरकाम के खिलाफ धारा 25 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, कथित 'बिच्छू गैंग' में सात से आठ युवक जुड़े होने की जानकारी मिली है। समूह से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने पर्यटकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। पुलिस ने अपील की है कि सरोधा बांध में किसी भी प्रकार की धमकी, जबरन वसूली या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पर्यटन स्थल पर भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

फसल रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर लगेगी लगाम, बलरामपुर में 99 अधिकारियों को सत्यापन की जिम्मेदारी!

बलरामपुर (जनता के गोठ) : बलरामपुर जिले में गिरदावरी एवं ई-गिरदावरी का कार्य शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा खसरों के भौतिक सत्यापन का आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार जिला, अनुभाग एवं तहसील स्तर के अधिकारियों को अलग-अलग प्रतिशत में खसरों की जाँच का दायित्व सौंपा गया है। आदेश के तहत कलेक्टर, वनमंडलाधिकारी और जिला पंचायत सीईओ सहित 39 जिला स्तरीय अधिकारी अपनी-अपनी तहसील के आवंटित ग्रामों में 1 प्रतिशत खसरों का सत्यापन करेंगे। इसी प्रकार 5 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने प्रभार क्षेत्र में 5 प्रतिशत, 19 तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 10 प्रतिशत तथा 13 कृषि विस्तार अधिकारी और 23 राजस्व निरीक्षक 25-25 प्रतिशत खसरों की जाँच करेंगे। सभी अधिकारियों को आवंटित ग्रामों के खसरों का सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बहुस्तरीय सत्यापन की इस व्यवस्था से फसल रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित होगी और किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक फसल स्थिति के आधार पर मिल सकेगा।

शंकरगढ़ में मोतियाबिंद मरीजों के लिए पहल, 60 मरीज ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल रवाना

बलरामपुर (जनता के गोठ) : कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में सेवा सेतु अभियान के तहत आकांक्षी विकासखंड शंकरगढ़ में मोतियाबिंद मुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। 13 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से मोतियाबिंद से पीड़ित 60 मरीजों को ऑपरेशन के लिए जिला चिकित्सालय बलरामपुर भेजा गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराना और उनकी आंखों की रोशनी बेहतर करने की दिशा में पहल करना है। मरीजों की पहचान से लेकर उन्हें जिला चिकित्सालय तक पहुंचाने में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



इस अभियान में नेत्र सहायक अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी, सभी सेक्टर प्रभारी, सेक्टर सुपरवाइजर, बीडीएम, मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी एवं मितानिनों का सराहनीय योगदान रहा। टीम के समन्वित प्रयासों से मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल भेजने की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष चिंतामणि भगत, खंड चिकित्सा अधिकारी शंकरगढ़ डॉ. आफ्ताब अंसारी एवं बीपीएम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सेवा सेतु अभियान के तहत संचालित यह पहल क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब मरीजों के ऑपरेशन और उपचार के बाद उनकी आंखों की रोशनी में सुधार की उम्मीद है।

ज्ञानेश कुमार के पुतले को हथकड़ी पहनाकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, SIR पर उठाए सवाल

कवर्धा में नवीन जायसवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च, चुनावी पारदर्शिता की मांग को लेकर किया पुतला दहन

कवर्धा: कबीरधाम जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्ट्रक्र और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्रतीकात्मक पुतले को हथकड़ी पहनाकर प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया।

कवर्धा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कबीरधाम ने शहर में पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस भवन से शुरू हुआ मार्च अंबेडकर गार्डन स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक पहुंचा।



यहां कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्रतीकात्मक पुतले को हथकड़ी पहनाकर पुतला दहन किया।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि लोकतंत्र में मताधिकार की सुरक्षा और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने, नए मतदाताओं के पंजीकरण और स्ट्रक्र की प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब पारदर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

जायसवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस की 25 सितंबर 2026 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री के इस्तीफे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष और जवाबदेह होनी चाहिए।

भानपुरी में 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत' विषय पर नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन

बकावंड जनता के गोठ। मेरा युवा भारत बस्तर, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भानपुरी में नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट नशा मुक्त युवा

फोर विकसित भारत कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना तथा नशा मुक्त और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था।



कार्यक्रम के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी (क्विज) एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला। साथ ही, उन्हें नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक नुकसान की जानकारी देते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती वेदवती कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष उपस्थित रहीं। इसके साथ ही श्री निर्देश दीवान, जिला पंचायत सदस्य, श्री रमेश प्रभाकर, सहायक उपनिरीक्षक (स्टू) तथा प्राचार्य श्री टी. के. दुर्गम सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अतिथियों ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और विकसित भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल, कौशल विकास एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपने परिवार, गांव और समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने तथा एक स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील की।

इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम ने युवाओं को नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया।

पांच विषयों में शिक्षक नहीं, कैसे संवरेगा मुरकौल के बच्चों का भविष्य?

एनएसयूआई का शिक्षा विभाग को 7 दिन का अल्टीमेटम, मांग पूरी नहीं हुई तो सड़क पर उतरेगा संगठन!

बलरामपुर (जनता के गोठ) : सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के दावों के बीच शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरकौल में शिक्षकों की कमी का मामला सामने आया है। विद्यालय में रसायन विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी जैसे पांच महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों का अभाव होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही गई है। इस स्थिति को लेकर एनएसयूआई ने शिक्षा विभाग के सामने मोर्चा खोलते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर को आवेदन सौंपा है और सात दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग की है।

पांच विषयों में शिक्षक नहीं, विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल!

आवेदन में कहा गया है कि शिक्षकों की कमी के कारण पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इसका असर विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी और आगामी बोर्ड परीक्षाओं पर पड़ने की आशंका है। सवाल यह है कि जब महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं,



तो विद्यार्थियों की तैयारी कैसे पूरी होगी? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

सिर्फ आश्वासन नहीं, चाहिए ठोस कार्रवाई

एनएसयूआई ने जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि विद्यालय में रिक्त शिक्षक पदों पर जल्द नियुक्ति की जाए। स्थायी नियुक्ति होने तक वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित न हो। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रखने के बजाय जमीनी स्तर पर समाधान किया जाना चाहिए।

7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी

एनएसयूआई ने शिक्षा विभाग को सात दिनों के भीतर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर हस्ट्ठ और विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इससे स्पष्ट है कि संगठन अब इस मुद्दे पर विभाग से जवाब और कार्रवाई चाहता है।

शिक्षा विभाग से सीधे सवाल—कब भरे जाएंगे रिक्त पद? मुरकौल विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर अब शिक्षा विभाग की भूमिका पर नजरें टिकी हैं। क्या विभाग बोर्ड परीक्षाओं से पहले पढ़ाई की व्यवस्था दुरुस्त करेगा? क्या रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी या विद्यार्थियों को शिक्षक मिलने का इंतजार ही करना पड़ेगा? क्या स्थायी नियुक्ति तक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी?

इन सवालों पर शिक्षा विभाग का जवाब और उसकी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। विद्यार्थियों का भविष्य किसी भी प्रशासनिक देरी की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। अब देखना होगा कि सात दिनों की समय-सीमा के भीतर विभाग कोई ठोस कदम उठाता है या एनएसयूआई को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है।

प्रदर्शन की चेतावनी का दिखा असर, सुशील मौर्य बोले–जनहित की लड़ाई में कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी

अल्टीमेटम से पहले झुका निगम प्रशासन नयापारा सड़क का निर्माण शुरू कांग्रेस के चक्काजाम और अनिश्चितकालीन धरना

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ

जगदलपुर शहर के मोतीलाल नेहरू वार्ड अंतर्गत नयापारा की सड़क का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के लगातार संघर्ष, चक्काजाम और आंदोलन की चेतावनी के बाद सड़क निर्माण शुरू होने को कांग्रेस ने अपनी जनहित की लड़ाई और वार्डवासियों की एकजुटता की जीत बताया है। पार्टी का दावा है कि प्रस्तावित चक्काजाम के एक सप्ताह पहले ही तथा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए दिए गए अल्टीमेटम की समयसीमा समाप्त होने से पहले ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया।



इस संबंध में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि नयापारा सड़क का निर्माण शुरू होना कांग्रेस पार्टी की जनहित के प्रति प्रतिबद्धता और वार्डवासियों की एकजुटता का परिणाम है। कांग्रेस लगातार आम जनता की समस्याओं को उठाती रही है और आगे भी जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेगें

जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा

सुशील मौर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। ऐसे में महापौर और विधायक की जिम्मेदारी है कि वे जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें और उनका समय पर निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के महापौर और विधायक जनता की समस्याओं के प्रति अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं।

मौर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य केवल विरोध प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराना है। नयापारा सड़क निर्माण कार्य शुरू होना इस बात का उदाहरण है कि जब जनता अपनी मांगों को लेकर एकजुट होती है और जनहित के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई जाती है, तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ती है।

पदाधिकारियों और वार्डवासियों को दी बधाई

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने इस सफलता के लिए कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नयापारा के वार्डवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी सड़क, पेयजल, सफाई सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के अधिकारों की लड़ाई में कांग्रेस न कभी पीछे हटी है और न ही भविष्य में पीछे हटेगी। पार्टी जनसमस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी, ताकि आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह बनें।

मंदिर में पूजा सामग्री बेचकर आत्मनिर्भर बन रहीं बिहान की महिलाएं

माता हिंगलाजिन गिरोला मंदिर में स्वरोजगार की मिसाल बनीं 8 स्वयं सहायता समूहों की दीदियां, पर्वों पर दोगुना होता है कारोबार



ओमप्रकाश रजक /जनता के गोठ/ जगदलपुर, । बस्तर जिले के ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जनपद पंचायत बकावंड के ग्राम पंचायत गिरोला स्थित माता हिंगलाजिन मंदिर में पूजा सामग्री का विक्रय कर बिहान से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार की नई मिसाल पेश कर रही हैं। इससे उन्हें नियमित आमदनी मिलने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी मदद मिल रही है।

माता हिंगलाजिन मंदिर में वर्षभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इसी अवसर को आजीविका का माध्यम बनाते हुए स्थानीय महिलाओं ने वर्ष 2018 में मंदिर परिसर में पूजा सामग्री बेचने की पहल शुरू की थी। बिहान योजना के तहत समूहों को आरएफ, सीआईएफ, सीईएफ और बैंक लिंकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके बाद महिलाओं ने संगठित होकर कारोबार को आगे बढ़ाया।

वर्तमान में 8 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं मंदिर परिसर में चुनरी, नारियल, अगरबत्ती, रोली, मौली, रुई बत्ती, फूल और प्रसाद सहित विभिन्न पूजन सामग्रियों की बिक्री कर रही हैं। समूहों की मासिक बिक्री सामान्य दिनों में 10 से 12 हजार रुपये तक पहुंच जाती है। नवरात्रि और अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से कारोबार और मुनाफे में भी दोगुनी वृद्धि होती है।

महिलाओं की मेहनत और एकजुटता से यह पहल अब उनकी आजीविका का मजबूत आधार बन गई है। बिहान योजना, जनपद पंचायत बकावंड और जिला प्रशासन के सहयोग से महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

सतीश मोरला बने ऑल इंडिया संपादक संघ के बीजापुर जिला अध्यक्ष

प्रेम कुमार दुर्गम जिला ब्यूरो प्रमुख बीजापुर बस्तर

बीजापुर। ऑल इंडिया संपादक संघ ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में संगठन को मजबूत करने की दिशा में सतीश मोरला को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। संघ की ओर से जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार, यह नियुक्ति 14 अक्टूबर 2026 को की गई है।



नियुक्ति पत्र में सतीश मोरला, पिता बाबू राव मोरला, निवासी ग्राम बोरजे, जिला बीजापुर को ऑल इंडिया संपादक संघ में जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। नियुक्ति पत्र पर संघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष धनश्याम यादव के हस्ताक्षर हैं।

संघ ने विश्वास जताया है कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने, पत्रकारों एवं संपादकों से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने तथा अनुशासित तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में योगदान देंगे। नियुक्ति पत्र के अनुसार, नियुक्ति की तिथि 14 अक्टूबर 2026 और वैधता 14 अक्टूबर 2027 तक निर्धारित है।

इस नियुक्ति से बीजापुर जिले में संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सतीश मोरला को सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए 30 अक्टूबर तक करें आवेदन

बलरामपुर (जनता के गोठ) : मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को तात्कालिक सहायता दी जाएगी, जिन्होंने शिक्षण सत्र 2026-27 में आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अथवा नीट और जेईई के माध्यम से प्रवेश प्राप्त किया है। पात्र विद्यार्थी अपने गृह जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में 30 अक्टूबर 2026 तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

बड़ॉंजी खासपारा में बाढ़ का कहर, 65 परिवार प्रभावित

किसी के मकान ढहे तो किसी की धान की फसल बर्बाद, संतु कश्यप ने प्रशासन से की उचित मुआवजे की मांग

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ

लोहण्डीगुड़ा । ग्राम बड़ॉंजी खासपारा में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने बस्तर ग्रामीण जिला अध्यक्ष संतु कश्यप, सचिव हरिराम कश्यप एवं परमेश्वर भारद्वाज गांव पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों के अनुसार, गांव के लगभग 65 परिवार बाढ़ की चपेट में आए हैं। किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, तो किसी किसान की धान की फसल बर्बाद हो गई है।

बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों के सामने घरों की मरम्मत, परिवार के भरण-पोषण और आगामी फसल की तैयारी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने फसल नुकसान के बदले प्रति हेक्टेयर मात्र 8,000 रुपये मुआवजा मिलने की बात पर चिंता जताई। उनका कहना है कि इतनी कम राशि से खेती में हुए नुकसान की भरपाई करना और अगली फसल की तैयारी करना मुश्किल है।



निष्पक्ष सर्वे कर प्रभावितों को मिले राहत- संतु कश्यप ने प्रशासन से मांग की कि गांव में बाढ़ से हुए नुकसान का निष्पक्ष सर्वे कराया जाए। जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं, जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी नियमानुसार राहत राशि उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामीण पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए समय पर सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि प्रभावित परिवार दोबारा सामान्य जीवन शुरू कर सकें। उन्होंने यह भी मांग की कि कोई भी पात्र परिवार राहत और मुआवजे से वंचित न रहे।

इस दौरान मोटू भारद्वाज, भागीरथी भारद्वाज, दामोदर भारद्वाज, भवानी, परमेश्वर, दुशासन, हीरामनी, फारसू भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

जनहित में 8 घंटे डटे रहे जनपद प्रतिनिधि ऋषिकांत बबलू पटेल, वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था कर दिलाई राहत

हथबंद रेलवे फाटक बंद होने की सूचना मिलते ही सक्रिय हुए जनप्रतिनिधि, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को मिली बड़ी राहत

जनता के गोठ/ओंकार साहू

बलौदाबाजार। हथबंद रेलवे फाटक 14 से 21 अक्टूबर 2026 तक आवश्यक सुधार कार्य के चलते बंद रहने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्रीय जनपद प्रतिनिधि ऋषिकांत बबलू पटेल ने जनहित में पहल करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मोर्चा संभाला। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर लगभग आठ घंटे तक मौके पर रहकर इस कार्य को अंजाम दिया। उनकी इस पहल से क्षेत्र के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों को राहत मिली,



वहीं लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऋषिकांत बबलू पटेल को मंगलवार रात करीब 10 बजे जानकारी मिली कि हथबंद रेलवे फाटक 14 से 21 अक्टूबर तक आवश्यक सुधार कार्य के लिए बंद रहेगा। फाटक बंद रहने से आवागमन में होने वाली संभावित परेशानियों को देखते हुए उन्होंने तत्काल हथबंद सरपंच और सीतापार सरपंच से चर्चा की। दोनों सरपंचों ने इस जनहित के कार्य में सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके बाद बबलू पटेल सुबह से ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के प्रयास में जुट गए और लगातार करीब आठ घंटे तक मौके पर रहकर कार्य को पूरा कराने में सहयोग किया।

इस जनहित के कार्य में हथबंद सरपंच प्रतिनिधि नरेश अनंत, सीतापार सरपंच प्रतिनिधि अकबर साहू, समाजसेवी अजय अग्रवाल, राममनोहर बांधे, सोनू साहू, सागर वर्मा, दुलेश्वर अनंत, शक्ति प्रजापति, रमी यादव, शुभम अग्रवाल और बिट्टू साव का विशेष सहयोग रहा। सभी के सामूहिक प्रयास से आवागमन की समस्या को कम करने की दिशा में पहल की गई।

जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी : बबलू पटेल

मोबाइल पर चर्चा के दौरान जनपद प्रतिनिधि ऋषिकांत बबलू पटेल ने कहा कि क्षेत्र की जनता के सुख-दुख में हम खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? आज जनता ने विश्वास जताकर हमें जनप्रतिनिधि चुना है, इसलिए उस विश्वास पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। हम हमेशा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहेंगे और जनहित के कार्यों में अपनी भागीदारी निभाते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि जैसे ही रेलवे फाटक बंद होने की जानकारी मिली, उन्होंने स्थानीय सरपंचों से चर्चा कर सहयोग मांगा और सुबह से ही व्यवस्था बनाने में जुट गए। उनके अनुसार, जनप्रतिनिधि होने का वास्तविक अर्थ जनता की जरूरत के समय उसके साथ खड़ा होना है।

बाढ़ प्रभावित किसानों ने दिया छह दिन का अल्टीमेटम, कर्जमाफी और मुआवजा बढ़ाने की मांग

फसल नुकसान का सर्वे कृषि ऋण माफी और मकान क्षति पर बढ़ी सहायता राशि की मांग

भुजबल बघेल

बकावंड जनता के गोठ। इंद्रावती और नारंगी नदी की बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने तहसीलदार बस्तर के माध्यम से मुख्यमंत्री, कलेक्टर और एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बोदरा, भैंसगांव, खोटलापाल और रोतमा के ग्रामीणों ने मांगों पर कार्रवाई के लिए छह दिन का अल्टीमेटम देते हुए समयसीमा में ठोस पहल नहीं होने पर शांतिपूर्ण आंदोलन की चेतावनी दी है।

ज्ञापन में बाढ़ से फसलों, कृषि भूमि और मकानों को हुए नुकसान का उल्लेख करते हुए प्रभावित क्षेत्रों



में स्थलीय सर्वे, आरबीसी 6-4 के तहत पात्र किसानों को मुआवजा, फसल बीमा से वंचित किसानों को विशेष राहत और कृषि ऋण माफी की मांग की गई है। ग्रामीणों ने आंशिक मकान क्षति पर सहायता राशि 6 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तथा पूर्ण क्षति पर 1.30 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की मांग भी रखी है। साथ ही छह दिनों के भीतर सर्वे की प्रगति, पात्र हितग्राहियों की सूची और राहत वितरण की समयसीमा स्पष्ट करने की मांग की गई है।

खाता संबंधी त्रुटियां सुधारकर राशि जारी की गई : तहसीलदार- तहसीलदार बस्तर ने बताया कि बाढ़ प्रभावित किसानों का सर्वे कर मुआवजा राशि उनके खातों में जमा कर दी गई है। खाता संबंधी और अन्य त्रुटियों के कारण कुछ लोगों को राशि नहीं मिल पाई थी। त्रुटियों में सुधार कर उनकी राशि भी जारी कर दी गई है। ग्रामीणों की मांगों से शासन को अवगत कराया जाएगा।

बेलपुटी-बारदा मार्ग पर बाढ़ से 15 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त, राहगीर परेशान



निर्माण के एक वर्ष के भीतर सड़क टूटने से गुणवत्ता पर उठे सवाल, मरम्मत और निष्पक्ष जांच की मांग

भुजबल बघेल

बकावंड जनता के गोठ। विकासखंड बकावंड के अंतर्गत बेलपुटी से बारदा जाने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्ग पर पुलिया के पास सड़क का करीब 15 मीटर हिस्सा बाढ़ के पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क का हिस्सा टूटकर बह जाने से इस मार्ग से आवागमन करने वाले ग्रामीणों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, सड़क का निर्माण करीब एक वर्ष पहले कराया गया था। इसके बावजूद बाढ़ के दौरान सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में कथित रूप से घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। हालांकि, निर्माण की गुणवत्ता को लेकर वास्तविक स्थिति संबंधित विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

आवागमन में दुर्घटना की आशंका



सड़क क्षतिग्रस्त होने से दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के साथ पैदल आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। सड़क का हिस्सा टूटने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ऐसे में ग्रामीणों को इस मार्ग से गुजरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है।

मरम्मत के साथ गुणवत्ता की जांच की मांग

ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से क्षतिग्रस्त सड़क का तत्काल निरीक्षण कराकर जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। साथ ही सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराने और अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का निर्माण हुए अभी करीब एक वर्ष ही हुआ है। ऐसे में सड़क का क्षतिग्रस्त होना चिंता का विषय है।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है ताकि आवागमन सुरक्षित हो सके और लोगों को राहत मिल सके ।

नायब तहसीलदार के खिलाफ एकजुट हुआ हिंदू समाज, 48 घंटे में हटाने की मांग

बलरामपुर (जनता के गोठ) : बलरामपुर जिले के कुसमी तहसील में नायब तहसीलदार द्वारा लगाया गया एक सूचना-पट्ट विवाद का कारण बन गया है। शारदीय नवरात्रि के दौरान तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार पर लिखवाया गया था - ÷तहसील परिसर में भिक्षा एवं चंदा मांगने वालों का प्रवेश वर्जित है।÷ इस बोर्ड के सामने आते ही हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया।

इस मामले को लेकर सकल हिंदू समाज और दुर्गा पूजा समितियों ने एसडीएम बालेश्वर राम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि नायब तहसीलदार अनुग्रह केरकेट्टा को 48 घंटे के भीतर कुसमी तहसील से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान इस तरह का बोर्ड लगाना हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। हिंदू समाज का कहना है कि नवरात्रि में दुर्गा पूजा समितियों द्वारा चंदा एकत्र किया जाता है, ऐसे समय में इस तरह का बोर्ड लगाना अशोभनीय है।



सोशल मीडिया में वायरल हुआ था बोर्ड, बाद में मिटवाया गया- बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार अनुग्रह केरकेट्टा द्वारा नवरात्रि के दौरान ही यह नोटिस लिखवाया गया था। जैसे ही इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को लगी, तहसीलदार ने तुरंत कर्मचारियों से पेंट कराकर सूचना-पट्ट को मिटवा दिया। लेकिन तब तक बोर्ड का फोटो नगर और सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था।

उग्र आंदोलन की चेतावनी

हिंदू समाज ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिवस के भीतर नायब तहसीलदार को नहीं हटाया गया तो सकल हिंदू समाज नगर बंद, चक्का जाम और तहसील कार्यालय का घेराव करने को बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर पंचायत उपाध्यक्ष आनंद जायसवाल, दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष जन्मजय सिंह, मां समलेश्वरी समिति अध्यक्ष जशवंत गुप्ता, मां भवानी समिति से विनय यादव, गोपाल गुप्ता, संजय गुप्ता, राजेश्वर गुप्ता, प्रदीप कश्यप, सुनील गुप्ता, बालेश्वर नायक, पार्षद पारसनाथ पाल, अमित सिंह भोलू सहित बड़ी संख्या में समाज प्रमुख उपस्थित रहे।

वहीं प्रशासन का कहना है कि नायब तहसीलदार ने किन परिस्थितियों में या किसके आदेश पर सूचना-पट्ट लगाया था, इसकी जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

भारतीय नाविकों की मौत, कब तय होगी जवाबदेही?

पश्चिम एशिया संघर्ष में 16 भारतीय नाविकों की मौत से चिंता बढ़ी। भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा और हमलों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ऊर्जा और आवश्यक वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने के साथ-साथ अब मानवीय संकट भी बढ़ता जा रहा है। समुद्री मार्गों में अपना प्रभाव मजबूत करने के लिए संघर्षरत पक्षों की ओर से भारत समेत अन्य देशों के नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, फारस की खाड़ी और काला सागर में हमलों के दौरान अब तक सोलह भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या किसी युद्ध में आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन नहीं है?क्या इन हमलों के लिए वैश्विक स्तर पर संबंधित पक्षों की जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए? दूसरी ओर, भारत के शासन की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बिना किसी उकसावे के हो रहे इन हमलों में भारतीयों की मौत पर महज औपचारिक चिंता व्यक्त करने के बजाय भारत को ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध दर्ज करना चाहिए।इसमें दोराय नहीं कि पश्चिम एशिया भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। फारस की खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीय देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान देते हैं। विदेश से भेजी जाने वाली उनकी कमाई देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत है। इसलिए इस क्षेत्र में संघर्ष और अस्थिरता का सीधा असर भारत के नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर पड़ना स्वाभाविक है।सरकार का दावा है कि होर्मुज जलमार्ग क्षेत्र से अब तक चार हजार से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग और फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों में जहाजों पर हमले लगातार बढ़े हैं। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, युद्ध में शामिल पक्षों के लिए सैनिकों और आम नागरिकों के बीच अंतर करना अनिवार्य है।किसी तीसरे देश के नागरिकों को निशाना बनाना भी नियमों के खिलाफ है।

चारधाम यात्रा के दौरान इस वर्ष सितंबर के मध्य तक 800 टन से अधिक कचरा एकत्र होने की सूचना इस संकट की गंभीरता को सामने रखती है। केदारनाथ जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त के बीच 50.30 टन कचरा जमा होना विशेष चिंता का विषय है। यह तथ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फेंकी गई एक प्लास्टिक बोतल केवल एक बोतल नहीं रहती, वह लंबे समय तक पर्यावरण में मौजूद रहकर मिट्टी, जलस्रोतों और वन्यजीवन के लिए खतरा बन सकती है। विडंबना देखिए-जिस स्थान पर मनुष्य आत्मशुद्धि, संयम और त्याग की भावना लेकर जाता है, वहीं वह अपने पीछे कचरे का निशान छोड़ आता है। क्या ऐसी यात्रा को वास्तव में तीर्थयात्रा कहा जा सकता है? तीर्थ का अर्थ केवल किसी मंदिर तक पहुंच जाना नहीं है। तीर्थ मनुष्य के भीतर परिवर्तन की यात्रा है। यदि मंदिर में माथा टेकने के बाद हम उसी पर्वत की गोद में प्लास्टिक फेंक दें, जिसकी पवित्रता के नाम पर वहां पहुंचे हैं, तो हमारी आस्था अधूरी रह जाती है।

हिमालय की प्रदूषण-मुक्ति भी हो पहाड़ी तीर्थयात्रा का उद्देश्य

(ललित गर्ग)

हिमाचल प्रदेश के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर भीड़ का अनियंत्रित बढ़ना इसी व्यापक संकट का हिस्सा है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, चामुंडा, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, नैना देवी और अन्य धार्मिक-पर्यटन स्थलों पर मौसम विशेष में बढ़ने वाला दबाव यातायात, जलापूर्ति, सीवेज, ठोस कचरा और स्थानीय संसाधनों पर असर डालता है।

हिमालय केवल पर्वतों की एक शृंखला नहीं है, वह भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक आस्था और प्राकृतिक जीवन का आधार है। उसकी चोटियों में तप की स्मृतियां हैं, उसकी नदियों में करोड़ों लोगों की जीवनधारा बहती है और उसकी घाटियों में असंख्य धार्मिक स्थल सदियों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे हिमालयी क्षेत्र में हिंदू धर्म के अनेक प्रमुख तीर्थस्थल हैं। इन स्थानों पर पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विषय है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले कुछ वर्षों में तीर्थयात्रा और पर्यटन के बीच की सीमा धुंधली होती जा रही है। दर्शन और आध्यात्मिक अनुभूति के साथ मनोरंजन, मौज-मस्ती और उपभोक्तावादी जीवनशैली का प्रवेश पहाड़ों की संवेदनशीलता पर भारी पड़ रहा है। हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। यहां का पर्यावरण अत्यंत नाजुक है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिट्टी की परत पतली है, वनस्पतियों की पुनरुत्पादन क्षमता सीमित है और कचरे के प्राकृतिक रूप से नष्ट होने की प्रक्रिया मैदानी क्षेत्रों की तुलना में बहुत धीमी है। इसके बावजूद हम हजारों-लाखों लोगों को एक साथ इन क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं। वाहनों की लंबी कतारें, पार्किंग का दबाव, होटल और ढाबों का अनियोजित विस्तार, प्लास्टिक की बोतलें, खाद्य पदार्थों के रैपर, पॉलीथिन और डिस्पोजेबल सामग्री पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं।

चारधाम यात्रा के दौरान इस वर्ष सितंबर के मध्य तक 800 टन से अधिक कचरा एकत्र होने की सूचना इस संकट की गंभीरता को सामने रखती है। केदारनाथ जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त के बीच 50.30 टन कचरा जमा होना विशेष चिंता का विषय है। यह तथ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फेंकी गई एक प्लास्टिक बोतल केवल एक बोतल नहीं रहती, वह लंबे समय तक पर्यावरण में मौजूद रहकर मिट्टी, जलस्रोतों और वन्यजीवन के लिए खतरा बन सकती है। विडंबना देखिए-जिस स्थान पर मनुष्य आत्मशुद्धि, संयम और त्याग की भावना लेकर जाता है, वहीं वह अपने पीछे कचरे का निशान छोड़ आता है। क्या ऐसी यात्रा को वास्तव में तीर्थयात्रा कहा जा सकता है? तीर्थ का अर्थ केवल किसी मंदिर तक पहुंच जाना नहीं है। तीर्थ मनुष्य के भीतर परिवर्तन की यात्रा है। यदि मंदिर में माथा टेकने के बाद हम उसी पर्वत की गोद में प्लास्टिक फेंक दें, जिसकी पवित्रता के नाम पर वहां पहुंचे हैं, तो हमारी आस्था अधूरी रह जाती है।



इस संदर्भ में 'कैरी मी बैक' अभियान उम्मीद की एक महत्वपूर्ण किरण है। लगभग पांच हजार तीर्थयात्रियों द्वारा करीब 18 किलोमीटर के रास्ते से 12 टन से अधिक कंप्रेस्ड प्लास्टिक वापस नीचे लाना बताता है कि श्रद्धालुओं को सहभागी बनाया जाए तो वे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह केवल कचरा उठाने का अभियान नहीं, बल्कि तीर्थयात्रा की मानसिकता बदलने का प्रयास है। ऐसे अभियानों को व्यापक स्वरूप देकर हिमाचल, उत्तराखंड और अन्य हिमालयी तीर्थ क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। अमरनाथ यात्रा से मिला अनुभव भी सकारात्मक दिशा दिखाता है। पुनः उपयोग किए जाने वाले बर्तनों और पानी भरने की सुविधाओं के विस्तार के कारण यात्रियों की संख्या में 17 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद प्रति यात्री कचरे में 15 प्रतिशत कमी आना इस बात का प्रमाण है कि सुविधाजनक और वैज्ञानिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए तो पर्यावरणीय दबाव कम किया जा सकता है। इसलिए केवल श्रद्धालुओं से अपील करना पर्याप्त नहीं है, प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार सबसे सहज विकल्प बने।

हिमाचल प्रदेश के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर भीड़ का अनियंत्रित बढ़ना इसी व्यापक संकट का हिस्सा है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, चामुंडा, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, नैना देवी और अन्य धार्मिक-पर्यटन स्थलों पर मौसम विशेष में बढ़ने वाला दबाव यातायात, जलापूर्ति, सीवेज, ठोस कचरा और स्थानीय संसाधनों पर असर डालता है। पहाड़ों की वहन क्षमता मैदानी शहरों जैसी नहीं है। इसलिए किसी भी तीर्थ या पर्यटन स्थल की लोकप्रियता को केवल अधिकाधिक लोगों को वहां पहुंचाने की सफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता। अब समय आ गया है कि 'जितने अधिक पर्यटक, उतना अधिक विकास' की सोच को 'जितना संवेदनशील पर्यावरण, उतना जिम्मेदार पर्यटन' में बदला जाए। तीर्थस्थलों की वहन क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन हो और उसके आधार पर प्रतिदिन या मौसम के अनुसार आगंतुकों की संख्या निर्धारित की जाए। सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रभावी नियंत्रण हो, पानी के रिफिल स्टेशन बढ़ाए जाएं, बोतलों और पैकेजिंग के लिए डिपॉजिट-रिटर्न व्यवस्था लागू की जाए तथा कचरे को स्रोत पर ही अलग करने की व्यवस्था हो। दुकानदारों, होटल संचालकों और वेंडरों को उनके द्वारा उत्पन्न कचरे के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण है तीर्थयात्री की मानसिकता में परिवर्तन। पहाड़ हमारे मनोरंजन के मैदान नहीं हैं। वे हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्राकृतिक विरासत हैं। जिस नदी के किनारे हम पूजा करते हैं, वही नदी नीचे बसे करोड़ों लोगों का जीवन है। जिस जंगल को हम कैमरे में कैद करते हैं, वही जंगल पहाड़ी पारिस्थितिकी को संतुलित करता है। जिस पर्वत को हम देवभूमि कहकर नमन करते हैं, उसकी ढलानों पर प्लास्टिक फेंकना हमारी अपनी श्रद्धा का अपमान है। नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में समय-समय पर अत्यधिक वर्षा, बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने यह चेतावनी दी है कि पर्वतीय पारिस्थितिकी के साथ छेड़छाड़ के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हर आपदा को सीधे पर्यटन या प्रदूषण का परिणाम मानना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि अनियोजित निर्माण, अत्यधिक मानवीय दबाव, वन क्षरण और कचरा प्रबंधन की कमजोरी पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है।

हिमालय आज चिन्ताओं का हिमालय बन गया है। कुछ दशकों में खासकर हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में विकास के नाम पर जहां प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है, वहीं धार्मिक पर्यटन के नाम पर व्यापक स्तर पर प्रदूषण फैला है। इतना ही नहीं, प्रकृति से खिलवाड़ कर नियमों के खिलाफ ऐसा निर्माण खड़ा किया जा रहा है, जो बाढ़ और भूस्खलन के साथ बर्बादी लेकर आता रहा है। सवाल यह भी है कि पहाड़ी राज्यों में विकास का क्या पैमाना होना चाहिए? अगर विकास के नाम पर कहीं निर्माण गतिविधियां आवश्यक हों तो वह नियोजन के साथ ही आपदाओं को झेलने में सक्षम होनी चाहिए। आम तौर पर देखा गया है कि इन राज्यों में पर्यटन एवं धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के नाम पर ऐसी बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हो गईं जो न सिर्फ बाढ़ और भूस्खलन झेलने में अक्षम साबित हुईं, बल्कि पर्यावरण के हिसाब से भी नुकसानदेह रही हैं। ऐसे निर्माण में सरकारी स्तर पर सतर्कता की जो उम्मीद की जाती है, उसे नजरअंदाज किया गया।

हिमालय हमें बहुत कुछ देता है-जल, वन, जैव विविधता, जलवायु संतुलन, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा। बदले में हमारी जिम्मेदारी केवल वहां जाकर पूजा करना नहीं, बल्कि उस प्रकृति की रक्षा करना भी है। तीर्थयात्री यदि एक बोतल पानी लेकर पहाड़ पर जा सकता है तो खाली बोतल वापस भी ला सकता है। यह छोटा-सा संकल्प बड़े परिवर्तन का आधार बन सकता है। आस्था और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। धार्मिक यात्रा का वास्तविक संस्कार तभी पूर्ण होगा जब तीर्थयात्री मंदिर से लौटते समय अपने साथ प्रसाद ही नहीं, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी लेकर लौटे। सरकारें व्यवस्था करें, स्थानीय समुदाय भागीदारी निभाएं और श्रद्धालु अपना कचरा वापस लाने का संकल्प लें-तभी हिमालय की पवित्रता सुरक्षित रह सकेगी। हिमालय को केवल देवभूमि कहने से उसकी रक्षा नहीं होगी, उसे देवभूमि की तरह व्यवहार देकर ही उसकी पवित्रता बचाई जा सकती है।

सितारों के विज्ञापन पर कौन रखेगा नजर? सेहत से खिलवाड़ करने वाले प्रचार पर जवाबदेही जरूरी

(मोनिका शर्मा)

पिछले दिनों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्मी कलाकारों से आग्रह किया कि वे ऐसी चीजों का प्रचार न करें, जिनसे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

यह व्यावहारिक तथ्य है कि लोकप्रियता अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। फिल्मी दुनिया हो या खेल जगत, राजनीति का पटल हो, समाज सुधार से जुड़े चर्चित व्यक्तित्व-कमोबेश सभी क्षेत्रों से जुड़े सफल चेहरों की बातें और बर्ताव न केवल चर्चा का विषय बनते हैं, बल्कि उनका अनुसरण करने की मानसिकता भी खूब देखने को मिलती है। विशेषकर युवाओं पर उनकी हर गतिविधि का असर होता है। लोकप्रिय चेहरों की ओर से आमजन को प्रभावित करने के इस मोर्चे पर फिल्मी सितारे सबसे आगे होते हैं।

यहां तक कि परदे पर दिखती कोई भूमिका भी लोगों के मन में उतर जाती है। उनके व्यक्तिगत जीवन की बातों का भी आमजन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच के कारण फिल्मी सितारों के माध्यम से आभासी मंचों पर परोसी गई सामग्री भी युवाओं के मानस पर दस्तक देने लगी है। पल-पल सामने आते अपने पसंदीदा चेहरों द्वारा किए गए विज्ञापन बहुत सरलता से उन्हें किसी बुरी लत, नकारात्मक बर्ताव या जीवन को असहज करने वाली आदत का अनुसरण करने के मार्ग पर धकेल देते हैं।

सेहत से खिलवाड़ करने वाले उत्पादों का प्रचार करते ही क्यों हैं?

पिछले दिनों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्मी कलाकारों से आग्रह किया कि वे ऐसी चीजों का प्रचार न करें, जिनसे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। जाहिर है, लोकप्रिय चेहरों का हानिकारक उत्पादों का प्रचार करना पूरी सामाजिक व्यवस्था पर असर डालता है। यही कारण है कि सोच-समझकर पूरे योजनागत ढंग से चर्चित हस्तियों को ऐसे प्रचार का हिस्सा बनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी कहा जा चुका है कि दुनिया भर में हर साल तंबाकू उत्पादों के सेवन से लगभग अस्सी लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। आम लोगों को बहकाने के लिए विज्ञापन रणनीतियों का सहारा लिया जाता है, जिन पर अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं।

इसमें दोराय नहीं कि नामी-गिरामी हस्तियों की खास छवि की जनमानस में गहरी पैठ होती है। जन-कल्याण से जुड़ी सजगता का संदेश देने वाले विज्ञापन हों या विशुद्ध व्यावसायिक उत्पादों का प्रचार, लोकप्रिय चेहरों की पहुंच और प्रभाव दोनों असरकारी साबित होते हैं। यही वजह है कि कंपनियां मोटी धनराशि चुकाकर इन सितारों को अपने उत्पादों के प्रचार के लिए चुनती हैं। इससे मिलने वाली रकम के लालच में अधिकतर चर्चित चेहरे बिना किसी मापदंड के किसी भी उत्पाद या सेवा के उपयोग की सलाह देते दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में किसी प्रचार के माध्यम से समाज को संदेश देने से पहले उसके असर को समझना लोकप्रिय चेहरों का दायित्व होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट और डब्ल्यूएचओ ने भी पहले चेताया है

आज की बदलती जीवनशैली में स्थान बना चुके बहुत से उत्पादों-सेवाओं के नुकसान किसी से छिपे नहीं हैं। विशेषकर मादक पदार्थों, शीतल पेय और अन्य तरह की ऑनलाइन गतिविधियों के खतरे जग-जाहिर हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ समय पहले तंबाकू उत्पादों की खुलेआम बिक्री पर कड़ी नाराजगी जताई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कई बार चेताया है कि धीमा जहर कहे जाने वाले तंबाकू उत्पाद कई जानलेवा बीमारियों की जड़ हैं।

शराब की आदत भी दुर्घटनाओं और अपराधों के आंकड़े बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्य बिगाड़ने तक कई जोखिम साथ लाती है। ऐसे में लोकप्रिय सितारों को जनता से मिले प्रेम, सराहना और विश्वास के भाव की अनदेखी करने के बजाय अपने दायित्व को समझना चाहिए। उन्हें हानिकारक उत्पादों का प्रचार कर उनका बाजार बढ़ाने की वकालत करने का रास्ता चुनने से बचना चाहिए।

कलाकारों को अपने प्रभाव के साथ ही कानून का सम्मान करते हुए किसी उत्पाद, व्यवहार या आदत का प्रचार करते समय अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रचार की मायावी दुनिया का खेल ही छलावे के दम पर चलता है। आमतौर पर इस छलावे का शिकार उपभोक्ता बनते हैं। गौर करने वाली बात है कि फिल्म और मनोरंजन जगत के जिन चर्चित चेहरों को लेकर उत्पाद या सेवा को प्रचारित किया जाता है, वे स्वयं इसका इस्तेमाल नहीं करते।

विशेषकर तब, जब कोई उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। यह दुखद है कि उत्पादों-सेवाओं के प्रचार को लेकर किसी भी तरह की जिम्मेदारी की भावना कभी रही ही नहीं। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा के कई सितारे पान मसाला और कई अन्य हानिकारक उत्पादों का प्रचार वर्षों से करते आ रहे हैं। कानूनी तौर पर भी ऐसे प्रचार को लेकर कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती है।

खेती के भविष्य से लेकर हमारी थाली तक अहम है बीज पर अधिकार का सवाल

वर्ष 2023 में सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी में सामने आया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पास आयातित फल-सब्जियों में जीएम उत्पादों की जांच का ठोस डेटा नहीं था। मई, 2025 में प्राधिकरण ने जीएम खाद्य पदार्थों के आयात पर परामर्श पत्र जारी किया, लेकिन निगरानी पर सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी थाली में क्या पहुंच रहा है? बीज का मसला खेत से अलग नहीं है। उसके साथ मिट्टी, पानी, खाद, कीटनाशक और खेती की पूरी लागत जुड़ी है।

(निमिषा सिंह)

बीजों की बदलती दुनिया में किसान के अधिकार, आत्मनिर्भरता, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा को बचाए रखते हुए नई कृषि तकनीकों और स्थानीय बीजों के बीच संतुलन बनाना क्यों जरूरी है। समय के साथ खेती बदली और इस बदलाव के साथ बीज की कहानी भी बदलती चली गई। आज बीज सिर्फ खेत में बोया जाने वाला दाना नहीं रह गया। उसके साथ बाजार, तकनीक, पेटेंट और कंपनियां जुड़ गई हैं। जाहिर है, जब बीज की दुनिया इतनी बदल गई, तो उस पर बहस भी होनी थी। यह बहस सिर्फ बीज की किस्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि किसान की पसंद, उसके अधिकार और खेती के भविष्य तक पहुंच गई। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे लौटना होगा-वहीं, जहां से खेती शुरू होती है, बीज से। पारंपरिक खेती में किसान अच्छी फसल से कुछ बीज अगली बुआई के लिए बचाकर रखता था। बेहतर किस्म के बीजों का आपस में आदान-प्रदान भी होता रहा। इससे अच्छे बीज एक किसान के खेत तक सीमित नहीं रहते थे। कौन-सा बीज किस मिट्टी में अच्छा फलेगा, कम पानी में कौन-सी किस्म टिकेगी और उसे वर्षों तक कैसे सुरक्षित रखना है, यह ज्ञान पीढ़ियों के अनुभव से बना था। यानी बीज सिर्फ फसल की शुरुआत नहीं, बल्कि किसान की अपनी तैयारी और आत्मनिर्भरता का हिस्सा था।

विकल्प बनाम निर्भरता – बीज जब खेत से निकलकर बाजार में पहुंचा, तो खेती



के बदलते दौर के साथ बीजों की दुनिया भी बदली। हरित क्रांति में अधिक उत्पादन देने वाली हाइब्रिड किस्मों और उन्नत बीजों का इस्तेमाल बढ़ा, जिनमें अलग-अलग किस्मों के अच्छे गुणों को संकरण के जरिए एक साथ लाने की कोशिश की जाती है। इससे कई फसलों में बेहतर पैदावार मिली, लेकिन अगली पीढ़ी में वही गुण कायम रहें, यह जरूरी नहीं है। ऐसे में किसान को नया बीज खरीदना पड़ सकता है। फिर सवाल उठा कि बदलते बीज बाजार ने किसानों के लिए विकल्प बढ़ाए हैं या उनकी आत्मनिर्भरता को कमजोर किया है। इसके बाद बहस जीएम यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों तक पहुंचती है। इनमें पौधे के आनुवंशिक गुणों में वैज्ञानिक तरीके से बदलाव कर कोई खास गुण लाने की कोशिश की जाती है- जैसे कीट प्रतिरोध, रोग-सहनशीलता या पोषण संबंधी गुण। भारत में जीएम बीजों की बहस मुख्यतः बीटी कपास के अनुभव से जुड़ी रही है, जिसके परिणामों को लेकर भी अलग-अलग मत हैं। जीएम फसलों के खुले में उत्पादन को लेकर चिंताएं कम नहीं हैं। आशंका है कि अगर ये फसलें खुले में उगाई गईं, तो पर-परागण के कारण भारत की मूल प्राकृतिक फसलें हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। इसी बीच, एचटी-बीटी जैसे अनधिकृत जीएम बीजों की बिक्री और खेती की खबरें भी सामने आती रही हैं। इससे एक बुनियादी सवाल उठता है कि जब अनधिकृत बीज नियमन से बाहर बाजार तक पहुंच सकते हैं, तो नई बीज तकनीकों की निगरानी और किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था कितनी मजबूत है?

स्वायत्तता का सवाल – यहीं से बीज की बहस एक विवादित तकनीक तक पहुंचती है- 'टर्मिनेटर सीड'। इसे 'जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी' कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें, तो इसमें पौधे की अगली पीढ़ी के बीजों को इस तरह तैयार किया जा सकता है कि वे दोबारा बोने लायक न रहें। यानी किसान फसल तो पैदा करे, लेकिन उसके बीज को संरक्षित कर अगली फसल के लिए इस्तेमाल न कर सके। इसी वजह से यह तकनीक किसान की बीज-स्वायत्तता और जैव विविधता को लेकर विवाद में है। देश में ऐसी तकनीक से तैयार बीज की किस्मों के पंजीकरण पर कानूनी रूप से रोक है। जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते में भी सावधानी का रुख अपनाते हुए पर्याप्त वैज्ञानिक आकलन के बिना ऐसे बीजों की खेती के परीक्षण और व्यावसायिक इस्तेमाल को मंजूरी न देने की बात कही गई है। इसलिए 'टर्मिनेटर सीड' आज भारत में कोई सामान्य कृषि तकनीक नहीं है, लेकिन इसकी बहस एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ती है कि खेती में बीज सिर्फ खरीदने-बेचने की वस्तु है या उस पर किसान का अपना अधिकार भी होना चाहिए?

सेहत की फिक्र – खेती और बीजों की बहस आखिरकार हमारी थाली और स्वास्थ्य से भी जुड़ती है। किसी फसल का हाइब्रिड और उन्नत या जीएम होना अकेले उसकी स्वास्थ्य-सुरक्षा तय नहीं करता। यह भी देखना जरूरी है कि उसे उगाने में क्या इस्तेमाल हुआ। भोजन में उसके अवशेष कितने बचे और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा। हर उत्पाद की अलग जांच जरूरी है। बहस डर की नहीं, जांच और पारदर्शिता की होनी चाहिए। वर्ष 2023 में सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी में सामने आया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पास आयातित फल-सब्जियों में जीएम उत्पादों की जांच का ठोस डेटा नहीं था।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सहसपुर लोहारा कॉलेज को दी 50 लाख के विकास कार्यों की सौगात

30 लाख के अतिरिक्त कक्ष का किया भूमिपूजन, बाउंड्रीवॉल और बालिका शौचालय के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की

युवा शक्ति संवाद में विद्यार्थियों को दिए सफलता के मंत्र कहाङ्क एआई को अपनी ताकत बनाएं, उस पर निर्भर नहीं रहें

कवर्धा, विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा के लिए अधोसंरचना मजबूत करने की दिशा में उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने आज शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा में 30 लाख रुपये की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय में 15 लाख रुपये की लागत से बाउंड्रीवॉल तथा 5 लाख रुपये की लागत से बालिका शौचालय निर्माण कराने की घोषणा की। महाविद्यालय में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर उन्हें अनुशासन, मेहनत और आधुनिक तकनीक के उपयोग से भविष्य संवारने के लिए प्रेरित किया।

अनुशासन और मेहनत से बनाएं भविष्यङ्क उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि युवा अपने लक्ष्य तय करें, अनुशासन में रहें और परिणाम की चिंता छोड़ मेहनत पर ध्यान दें। आधुनिक तकनीक सीखें, लेकिन उसके अधीन न हों। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने युवा शक्ति संवाद में विद्यार्थियों को यह संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज करियर बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र है। विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शर्मा ने बताया कि कवर्धा क्षेत्र के स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अब महाविद्यालयों में भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पीएससी, एसएससी और यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।

आधुनिक शिक्षा के साथ अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाना जरूरी

तकनीक और नवाचार पर बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के युवाओं को आधुनिक एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी और सोशल मीडिया की तकनीकी



समझ होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे इन तकनीकों का सही उपयोग कर इनका मास्टर बनें, न कि तकनीक को खुद का मास्टर बनने दें। आधुनिक तकनीक की समझ के साथ अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेहनत और तैयारी हमारे हाथ में हैं, इसलिए परिणाम की चिंता करने के बजाय प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। निरंतर अभ्यास, अनुशासन और धैर्य से ही सफलता का रास्ता बनता है। उन्होंने महाविद्यालय को विद्यार्थियों का अपना संस्थान बताते हुए कहा कि जिस तरह दीपावली पर हम अपने घर को संवारते हैं, उसी तरह विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलकर कॉलेज को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म में आने और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि अनुशासन जीवन में आगे बढ़ने की मजबूत नींव है। उन्होंने प्राचार्य और प्राध्यापकों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों से नियमित पढ़ाई करने, अपनी रुचि पहचानने और लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगरपालिका कवर्धा के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं साकम्बरी बोर्ड के सदस्य संतोष पटेल , लाला राम साहू, जनपद पंचायत लोहारा की अध्यक्ष दुर्गा ठाकुर, नगरपालिका लोहारा की अध्यक्ष सरिता मिश्रा, जिला पंचायत सभापति मनीराम साहू, विजय पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित थे।

नाबालिग पर चाकू से हमले के मामले में तीन युवकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई



कवर्धा। कबीरधाम जिले के ग्राम हरिनछपरा में सतनाम धूनी कार्यक्रम के दौरान नाबालिग बालक के साथ मारपीट और चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने तीनों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (ङ्कहस्स्) की धारा 170, सहपठित धारा 126 एवं 135(3) के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस के अनुसार, घटना 28 सितंबर 2026 की है। ग्राम हरिनछपरा में आयोजित सतनाम धूनी कार्यक्रम के दौरान गाली-गलौज करने से मना करने पर विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान एक नाबालिग बालक के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी देते हुए पेट में चाकू से वार कर घायल कर दिया गया। घटना के बाद घायल बालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल, कवर्धा ले जाया गया। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 433/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(3), 118(1) एवं 3(5) में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने और संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए कृस्टल गर्ग, कुनाल चतुर्वेदी और समीर पात्रे, निवासी ग्राम भालूचुवा, थाना भोरमदेव, जिला कबीरधाम के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन और डीएसपी मुख्यालय आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा की टीम मामले में कार्रवाई कर रही है। कबीरधाम पुलिस ने नागरिकों से धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थलों पर शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार आपके द्वार '' शिविरों का आयोजन केन्द्र व राज्य सरकार की गहरी संवेदनशीलता का परिचायक – उद्योग मंत्री

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा के दर्री जोनांतर्गत आयोजित शिविर को संबोधित करते हुये प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज कहा कि '' सरकार आपके द्वार '' शिविरों का आयोजन केन्द्र एवं राज्य सरकार की गहरी संवेदनशीलता का परिचायक है, उन्होने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवाकाल के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में '' सेवा संकल्प अभियान व सेवा सेतु अभियान '' के तहत यह शिविर लगाये जा रहे हैं, इन शिविरों के माध्यम से जहॉ एक ओर आमनागरिकों की शिकायतों व समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन व नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा '' सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत सेवा सेतु अभियान '' के तहत निगम के सभी जोन में क्रमशः ''सरकार आपके द्वार'' शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, शिविर आयोजन की इस कड़ी में निगम के दर्री जोन कार्यालय में शिविर आयोजित किया गया। प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन व महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने शिविर में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुये शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाये स्टालों का निरीक्षण किया। इस मौके पर सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, आयुक्त आशुतोष पाण्डेय सहित मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षद व एल्डरमेनगण विशेष रूप से उपस्थित थे। शिविर को संबोधित करते हुये उद्योग मंत्री देवांगन ने आगे कहा कि हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवाकाल के 25 वर्ष ऐतिहासिक रहे हैं, वे 13 वर्षो तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तथा अब 12 वर्षो से देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में देश के विकास में ऐतिहासिक कार्य हुये हैं। उन्होने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटलबिहारी वाजपेयी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अब छत्तीसगढ़ को संवार रहे हैं। केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसका सीधा लाभ करोड़ों लोगों को प्राप्त हो रहा है। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने आगे कहा कि डॉ.रमन सिंह ने 15 वर्षों के अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक रूप से विकास किया, जनहितकारी योजनाएं चलाई और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों तक पहुंच रहा शिविरों का प्रत्यक्ष लाभ - इस मौके पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवाकाल के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित '' सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत सेवा सेतु अभियान '' के तहत आयोजित किये जा रहे '' सरकार आपके द्वार '' शिविरों का प्रत्यक्ष लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होने कहा कि नगर निगम कोरबा आमजनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, एक ओर जहॉ समस्याएं तेजी से दूर की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओ अरबों रूपये के छोटे-बड़े विकास कार्य कराये जा रहे हैं। शिविरों में शिकायतों व समस्याओं से जुड़े आवेदन कम आना, इस बात का प्रमाण है कि समस्याओं को दूर करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। उद्योग मंत्री व महापौर का मिल रहा लगातार मार्गदर्शन- इस मौके पर सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत का लगातार मार्गदर्शन जनसमस्याओं को दूर करने व नगर विकास की दिशा में प्राप्त हो रहा है तथा उन्हीं के दिशा निर्देशन में निगम के अधिकारी कर्मचारी नागरिकों की समस्याओं को दूर करने व नगर के सर्वांगीण विकास के लिये अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं।

बिर्रा में जसगीत का भव्य आयोजन



कमल खुंटे/जनता के गोठ

बिर्रा। जय दुर्गे नाटक मंडली दुर्गा उत्सव समिति दीवान मोहल्ला बिर्रा द्वारा शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ जगदम्बा की कृपा से संगीतमय जसगीत का आयोजन किया गया है, जिसमें आचार्य नवरतन पाण्डेय एवं जोत रक्षक सुदर्शन दास बैष्णव हैं। कार्यक्रम के तहत 15 अक्टूबर गुरुवार को जसगीत पार्टी सोनादह, 16 अक्टूबर शुक्रवार को जय माँ चंडी झांकी पार्टी बिर्रा (प्रायोजक केशरवानी हार्डवेयर), 17 अक्टूबर शनिवार को डांस प्रतियोगिता, 18 अक्टूबर रविवार को हितेश चंद्रा म्यूजिकल ग्रुप काशीगढ़ (प्रायोजक कान्हा बोरवेल व दिलीप पाण्डेय), 19 अक्टूबर सोमवार को बाली सुग्रीव जसगीत पार्टी मिरौनी बैराज (प्रायोजक दीवान फ्यूल्स प्रो. चेतन प्रताप सिंह/पीयूष देव सिंह सोनू बाबा) एवं 20 अक्टूबर मंगलवार को माँ दुर्गा विसर्जन होगा। आयोजन दीवान, पटेल, थावाईत, धीवर मोहल्ला, घनवा पारा, फुलवारी पारा व समस्त ग्रामवासी बिर्रा द्वारा किया जा रहा है।

कटघोरा-अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर घंटों जाम, एनएचएआई अधिकारियों के खिलाफकोर्ट में परिवाद

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नेशनल हाईवे-130 पर मदनपुर घाट के पास ट्रेलर दुर्घटना के बाद लगे लंबे जाम को लेकर पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया है। पुलिस का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने जाम हटाने और यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 222ए के तहत कटघोरा न्यायालय में परिवाद पेश किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 2.30 बजे बांगो थाना क्षेत्र के मोरगा चैकी अंतर्गत मदनपुर घाट में नेशनल हाईवे-130 पर एक ट्रेलर खराब होकर खड़ा था। ट्रेलर क्रमांक ब्ळ्10ठै5980 तारा घाटी से कटघोरा की ओर आ रहा था। इसी दौरान तारा घाटी से अंबिकापुर की ओर जा रहे दूसरे ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 बीएस 9436 के चालक ने कथित तौर पर लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क पर खड़े खराब ट्रेलर को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद बिलासपुर-अंबिकापुर मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

जाम के कारण बसों में सफर कर रहे यात्रियों के साथ-साथ एंबुलेंस से उपचार के लिए जा रहे मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ट्रेन और हवाई यात्रा के लिए निकले यात्रियों, महिलाओं और बच्चों को भी लंबे समय तक सड़क पर फंसे रहना पड़ा। पुलिस के मुताबिक, जाम की स्थिति से निपटने के लिए बांगो थाना और मोरगा चैकी का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हाईवे पेट्रोलिंग और 112 की टीम के सहयोग से यातायात बहाल करने का प्रयास किया गया।

पुलिस का कहना है कि जाम हटाने में सहयोग के लिए एनएचएआई के अधिकारियों को फोन के माध्यम से सूचना दी गई थी, लेकिन तत्काल प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं मिली। आरोप है कि कई घंटे तक यात्रियों को परेशानी होती रही और जाम के समाधान के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। इसी आधार पर पुलिस ने एनएचएआई के अधिकारियों पर अपने दायित्वों के निर्वहन में सहायता नहीं करने का आरोप लगाते हुए कटघोरा न्यायालय में ठछै की धारा 222ए के तहत परिवाद दायर किया है।

चोरभट्ठी स्कूल में बच्चों से सभापति का सवाल जवाब, स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा जरूरी – नूतनसिंह

कोरबा। विधानसभा कोरबा क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित चोरभट्ठी गांव के प्राथमिक शाला पहुंचकर नगर निगम कोरबा सभापति नूतनसिंह ठाकुर ने छोटे बच्चों से मिलकर उनको प्रोत्साहित किया।

शासकीय स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से चालू किए गए चालू मुहिम सभापति की पाठशाला में आज शासकीय प्राथमिक शाला चोरभट्ठी में निगम सभापति नूतनसिंह ठाकुर ने बच्चों से मिलकर सवाल जवाब किया। । नन्हे बच्चों ने खेल, कला, अंग्रेजी विषय पर सवालो? को मासूमियत से जवाब दिया। सभापति नूतनसिंह ठाकुर के साथ एमआईसी सदस्य किशनलाल कैवर्त, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती सम्मत कंवर, रतन सिंह, शाला की शिक्षिका भुनेश्वरी राठौर उपस्थित रहीं। इस अवसर पर नियमित रूप से स्कूल आने वाले तथा प्रतिभाशाली बच्चों शुभम, शिवांगी, सुहानी , आयुष, को पुरस्कृत किया गया।

शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के प्रतिभा को उभारने, बच्चों को नैतिक और सामान्य ज्ञान की शिक्षा देने, उनके बीच परीक्षा के डर को खत्म करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के विकास के लिए नूतनसिंह ठाकुर ने सभापति की पाठशाला मुहिम लगातार चल? रहा है जिसमें जनप्रतिनिधियों को शासकीय स्कूलों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने में मददगार साबित हो रहा है। जनप्रतिनिधियों को अपने बीच पाकर तथा पुरस्कार पाकर स्कूली बच्चो में खुशियां दुगना हो जाता है। चोरभट्ठी गांव में स्थित प्राथमिक शाला में मात्र दो कमरों में पांचवीं तक कक्षाएं संचालित है, अभावों के बीच भी वहां पढ़ने वाले बच्चों के सपने शहरी बच्चों से कम नहीं है। नूतनसिंह ठाकुर एवं पार्षद श्रीमती सम्मत कंवर ने एनटीपीसी के आश्रित गांव के प्राथमिक स्कूल में समस्याओं को दूर करने की मांग जिला प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधन से किया है।

मुरकौल स्कूल में शिक्षकों का टोटा, विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट! एनएसयूआई ने शिक्षा विभाग को सौंपा ज्ञापन

रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग, एनएसयूआई ने कहा– विद्यार्थियों की पढ़ाई से समझौता बर्दाश्त नहीं



बलरामपुर (जनता के गोठ) : शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरकौल में शिक्षकों की कमी का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। विद्यालय में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कमी को दूर करने और विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू कराने की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई), विधानसभा प्रतापपुर ने शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया है। एनएसयूआई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर के नाम ज्ञापन विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर के माध्यम से सौंपकर जल्द आवश्यक कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई ने विद्यालय में शिक्षकों की कमी को विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शिक्षा विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी का सामना न करना पड़े और उनकी शैक्षणिक तैयारी प्रभावित न हो।

ज्ञापन सौंपकर उठाई आवाज, अब कार्रवाई का इंतजार

एनएसयूआई पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि शिक्षा विभाग इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द कदम उठाएगा। अब देखना होगा कि विभाग विद्यालय में शिक्षकों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर रिक्त पदों को भरने के लिए कब तक ठोस पहल करता है। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केवल आश्वासन नहीं, बल्कि समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है।

इस दौरान एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष अतुल यादव, रामदेव जगते, आशीष यादव, हरिओम यादव, ऋतिक यादव, मनलेश जगते और एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष प्रियांशु जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री ने सहसपुर लोहारा में 48 लाख के एसडीएम कार्यालय भवन का किया लोकार्पण

नए भवन से प्रशासनिक कार्यों को मिलेगी गति, नागरिकों को शासकीय सेवाओं में होगी सुविधा

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा– जनता के काम समय पर हों, प्रशासन में पारदर्शिता और संवेदनशीलता रहे



कवर्धा: सहसपुर लोहारा में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और नागरिकों को बेहतर शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने आज 48 लाख रुपए की लागत से एसडीएम कार्यालय नवीन भवन का लोकार्पण किया। नए भवन के शुरू होने से अनुविभागीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के संचालन को बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में शासकीय सेवाओं की व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के चहुंमुखी विकास और आम नागरिकों को बेहतर शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व संबंधी मामले सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए इनके निराकरण में समयबद्धता और पारदर्शिता बेहद जरूरी है।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों-कर्मचारियों से कहा कि वे स्वयं को जनता का सेवक मानकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और उनके काम समय पर पूरे हों। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के मैदानी कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है।

उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सूतियापाठ स्थित मां हिंगलाज माता मंदिर के जीर्णोद्धार और ग्राम मोतिमपुर से मंदिर तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 9 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन कार्यों से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी और धार्मिक स्थल का विकास होगा। उन्होंने बताया कि कवर्धा में बिलासपुर रोड और रायपुर रोड से शहर के भीतर प्रवेश करने वाले मार्गों पर 54 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही माता विंध्यवासिनी मंदिर और बूढ़ा महादेव मंदिर के विकास पर भी काम किया जा रहा है। महामाया मंदिर चौक से समनापुर तक सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्यों से क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि एसडीएम कार्यालय परिसर में बनाए गए किसान सदन में नागरिकों और किसानों के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां टेलीविजन, आरामदायक कुर्सियां, वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि कार्यालय आने वाले किसानों को इंतजार के दौरान असुविधा न हो। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगरपालिका कवर्धा के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं शाकम्बरी बोर्ड के सदस्य संतोष पटेल जी, लाला राम साहू, जनपद पंचायत लोहारा की अध्यक्ष दुर्गा ठाकुर, नगरपालिका लोहारा की अध्यक्ष सरिता मिश्रा, जिला पंचायत सभापति मनीराम साहू, नगरपालिका लोहारा के उपाध्यक्ष हेमंत साहू, उमंग पांडे , जलेश्वर वर्मा, रेखचंद पटेल, परदेशी पटेल, रवि राजपूत, चंद्रन पटेल और विजय पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी सहित आम नागरिक उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

बेटे और अफेयर पर खामोशी के लिए 336 करोड़ किए ऑफर? मस्क की पूर्व प्रेमिका एशले का दावा

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका की जानी-मानी दक्षिणपंथी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखिका एशले सेंट क्लेयर ने अमेरिकी अरबपति व टेस्ला प्रमुख एलन मस्क के साथ खुद के संबंधों पर बेहद चौकाने वाला खुलासा किया है। एशले ने कहा है कि उन्हें मस्क ने अपने रिश्ते



और बच्चे पर खामोश रहने के लिए लगभग 336 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने तुरंत ठुकरा दिया था। एशले ने कहा कि वह नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा पूरी जिंदगी एक गंदा रहस्य बनकर जिए। एशले ने दावा किया कि उनके बेटे रॉमुलस के जन्म के बाद मस्क की तरफ से उन्हें यह सीक्रेट डील ऑफर की गई थी। इसके तहत उन्हें तुरंत करीब 126 करोड़ रुपये नकद और अगले 21 वर्षों तक हर महीने 84 लाख रुपये दिए जाने थे। एशले ने ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता एलेक्स गिबनी की डॉक्यूमेंट्री मस्क और द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मस्क के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की है।

जिबूती में प्रवासियों से भरी नाव पलटी, 15 बच्चों समेत 109 लोगों की मौत

जिबूती , एजेंसी। पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती के तट के पास 305 लोगों को ले जा रही एक नौका पलट गई, जिसके कारण कम से कम 109 प्रवासियों की मौत हो गई। मृतकों में 15 बच्चे भी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने रविवार को यह जानकारी दी। आईओएम के अनुसार, नौका बृहस्पतिवार रात



या शुक्रवार सुबह जिबूती से यमन जा रही थी, तभी वह पलट गई। इस हादसे में 52 पुरुषों, 42 महिलाओं और 15 बच्चों की मौत हुई। 80 से अधिक लोग बच गए, जबकि कम से कम 116 अन्य लोग अब भी लापता हैं।

संगठन ने अपने एक बयान में कहा कि अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र से हर साल हजारों प्रवासी सुरक्षित ठिकानों और रोजगार के अवसरों की तलाश में जिबूती से होते हुए बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य पार कर खाड़ी देशों की ओर जाते हैं। यमन में हिंसा जारी रहने के बावजूद प्रवासियों का यह आवागमन जारी है।

जिबूती में आईओएम के मिशन प्रमुख अलेक्जेंड्रे कोइसाक ने कहा, यह जानमाल का बेहद दुखद नुकसान है। यह त्रासदी उन खतरों की गंभीर याद दिलाती है, जिनका सामना प्रवासियों को रोजगार के अवसरों की तलाश में इस प्रवासन मार्ग पर करना पड़ता है।

बांग्लादेश में रवींद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर काली स्याही पोती, हिरासत में चार आरोपी

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कवि रवींद्रनाथ टैगोर की ग्रैफिटी (दीवार पर बनी तस्वीर) खराब करने का मामला सामने आया है। बांग्लादेश शिल्पकला अकादमी के बाहर बनी नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर शनिवार को काली स्याही पोत दी गई। ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस के रमना डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर शेख जाहिदुल इस्लाम ने बताया कि इस मामले में महिला समेत चार लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आरोपितों के नाम और पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।

घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें एक महिला ब्रश से टैगोर की तस्वीर पर काली स्याही लगाती दिख रही है। शाहबाग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर महिला को वहां से हटाया। हंगामे के बाद पुलिस ने महिला और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया और वैन में ले गई।

फिलीपीन में बच्चों के यौन शोषण का खौफनाक नेटवर्क, कैमरे के सामने परोसा जा रहा बचपन

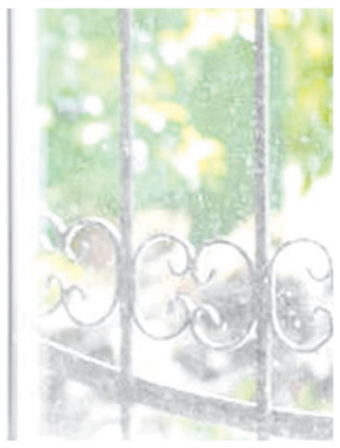
मनीला/वॉशिंगटन, एजेंसी। डिजिटल क्रांति के दौर में जहां दुनिया एक-दूसरे के करीब आई है, वहीं तकनीक का एक ऐसा घिनौना और खौफनाक चेहरा भी सामने आ रहा है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। द्वीपीय देश फिलीपीन में गरीबी का फायदा उठा मासूमों को बाल यौन शोषण सामग्री में बदला जा रहा है। उन्हें अपने देश में यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है और अमीरों का शौक पूरा करने के लिए मीलों दूर स्थित शहरों में सीधे प्रसारित किया जाता है। सीएनएन की एक खोजी रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और यूरोप जैसे अमीर देशों में बैठे लोग इसके बदले में बड़ी रकम खर्च करते हैं।

फिलीपीन इस अवैध और खौफनाक ऑनलाइन नेटवर्क का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। 13 वर्ष की केट (बदला नाम) की कहानी इस भयावह सच्चाई को बयां करती है। कोविड-19 के दौरान जब केट के पिता की नौकरी चली गई और परिवार पाई-पाई को मोहताज हो गया तो



अपने ही कर रहे सौदा...एन्क्रप्टेड एप्स से मिला बढ़ावा

बच्चों का सौदा करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार वाले ही होते हैं। फिलिपिनो पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार दलालों में बड़ी संख्या उन माताओं की है, जिन्होंने आर्थिक तंगी के आगे अपने बच्चों का सौदा कर दिया। बच्चों का शोषण करने वाले खरीदार समाज के हर वर्ग से आते हैं। इनमें कॉलेज के छात्र, बिजनेसमैन, रेस्टोरेंट कर्मचारी से लेकर जलवायु सलाहकार और पढ़े-लिखे पेशेवर तक शामिल हैं। कई आरोपी तो ऐसे हैं जो खुद शादीशुदा हैं और जिनके घर में बच्चे व नाती-पोते हैं। पहले यह धंधा डार्क वेब तक सीमित था लेकिन अब टेलीग्राम, व्हाट्सएप और वाइबर जैसे एन्क्रिप्टेड एप्स तक फैल चुका है। टेलीग्राम पर तो खुलेआम ऐसे प्राइवेट ग्रुप चलते हैं जहां कैंडी, किड्डी जैसे सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल करके सामग्री की नुमाइश की जाती है।



परिवार को भुखमरी से बचाने के नाम पर उसकी गोद ली गई बड़ी बहन ने ही उसे कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। शुरुआती दिनों में केट से केवल विदेशी ग्राहकों के साथ बातचीत बातचीत का नाटक करने को कहा गया। लेकिन धीरे-धीरे मांगें बदलती गईं और ऐसे खौफनाक और हिंसक कृत्यों की मांग की जाने लगी, जिनकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

हर 100 में एक बच्चा झेल रहा प्रताड़ना

इंटरनेशनल जस्टिस मिशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिलीपीन में करीब 5 लाख बच्चों को ऑनलाइन यौन सामग्री बनने को मजबूर किया जाता है। हर 100 में से एक बच्चा ऐसे अवैध तस्करी नेटवर्क के जाल में फंसा है। 2020 से 2022 के बीच अमेरिकी नागरिकों ने फिलीपीन से इस तरह की अवैध और हिंसक सामग्री खरीदने के लिए 70 लाख डॉलर (लगभग 58 करोड़ रुपये) से अधिक की राशि खर्च कर डाली।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने कई तरह की चुनौतियां

अपराधी रिकॉर्डेड वीडियो की जगह लाइव स्ट्रीमिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइव प्रसारण खत्म होते ही कोई डिजिटल सबूत पीछे नहीं छूटता, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ठोस सबूत जुटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। एप्स की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तकनीक अपराधियों को एक मजबूत सुरक्षा घेरा प्रदान करती है। यही नहीं, प्रशासनिक और आंतरिक प्राथमिकताओं के चलते कई बार जांच धीमी पड़ने की वजह से भी अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं।

पाकिस्तान को विश्व बैंक का झटका: दक्षिण एशिया की सूची से नाम बाहर, भारत से तुलना खत्म होने पर मचा बवाल

न्यूयार्क, एजेंसी। विश्व बैंक के क्षेत्रीय वर्गीकरण में बदलाव को लेकर पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है। पाकिस्तानी पत्रकार शहबाज राणा के मुताबिक, पाकिस्तान को दक्षिण एशिया समूह से हटाकर मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले रूढ़िबद्ध समूह में शामिल किया गया है। हालांकि, इसे भारत की जीत या पाकिस्तान को दंडित करने का फैसला बताने के लिए ठोस प्रमाण सामने नहीं हैं। यह बदलाव विश्व बैंक की प्रशासनिक और क्षेत्रीय व्यवस्था से जुड़ा है।

विश्व बैंक के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 1 जुलाई 2025 से दक्षिण एशिया की श्रेणी से हटाकर मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में शामिल किया गया। इस बदलाव की पुष्टि विश्व बैंक के आँकड़ा पोर्टल और उसके दिसंबर 2025 के लेख में भी की गई है। दक्षिण एशिया के इस नए वर्गीकरण में अब भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल हैं।



पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग क्षेत्रीय समूह में रखा गया है। पाकिस्तानी पत्रकार शहबाज राणा ने अपने कार्यक्रम में इस बदलाव को भारत-पाकिस्तान तनाव और विश्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ी परिस्थितियों से जोड़कर चर्चा की। उनके अनुसार, नई दिल्ली में कार्यालय होने की स्थिति में पाकिस्तानी अधिकारियों को वीजा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। क्षेत्रीय वर्गीकरण बदलने से पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति या उसकी आय के आधार पर तय होने वाली आर्थिक श्रेणी अपने आप नहीं बदलती।

सरकारी खजाने से ट्रंप का प्रचार पड़ा भारी

जनता के पैसों से चल रहे विज्ञापनों पर कोर्ट ने लगाई रोक

वाशिंगटन एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने राजनीतिक संदेश के प्रचार के लिए सरकारी खजाने से चलाए जा रहे टीवी विज्ञापनों पर रोक लगानी होगी। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने रविवार रात प्रशासन को आदेश दिया कि ऐसे सभी विज्ञापन तुरंत बंद किए जाएं, जो अब भी प्रसारित होने बाकी हैं। खास बात यह है कि प्रशासन पहले ही कह चुका था कि विज्ञापन अभियान जल्द खत्म होने वाला है। इसके बावजूद अदालत ने साफ कर दिया कि रविवार रात प्रसारित होने वाले विज्ञापनों समेत बाकी सभी विज्ञापनों को भी रद्द करना होगा।

जनता के पैसे से राजनीतिक प्रचार पर उठे सवाल- यह पूरा मामला उन टीवी विज्ञापनों से जुड़ा है, जिन पर करदाताओं के लाखों डॉलर खर्च किए गए। इन विज्ञापनों के जरिए ट्रंप के राजनीतिक संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। इस खर्च पर सवाल उठाते हुए एक गठबंधन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस गठबंधन में गैर-दलीय निगरानी संगठन कॉमन कॉज भी शामिल था। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकारी धन का इस तरह इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है और इसे सार्वजनिक धन का अनुचित इस्तेमाल माना जाना चाहिए। न्यूयॉर्क की अमेरिकी जिला अदालत की जज जेनिफर एल. रोचोन ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए प्रशासन के खिलाफ फैसला सुनाया। उन्होंने अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसके तहत प्रशासन को बचे हुए सभी टीवी विज्ञापन रद्द करने होंगे। इस आदेश में उन विज्ञापनों को भी शामिल किया गया, जिनका प्रसारण रविवार रात होना था। यानी प्रशासन की ओर से विज्ञापन अभियान खत्म करने की घोषणा के बावजूद अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया कि कोई भी बाकी विज्ञापन प्रसारित न हो।



अब सरकारी खर्च और राजनीतिक संदेश के इस्तेमाल पर नजर

इस मामले ने सरकारी धन के इस्तेमाल और राजनीतिक प्रचार के बीच की सीमा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत करने वाले संगठनों का कहना है कि जनता के पैसे का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता, जिसे वे किसी राजनीतिक संदेश को बढ़ावा देने का अनुचित तरीका मानते हैं। अदालत के आदेश का तत्काल असर यह है कि प्रशासन को बचे हुए विज्ञापनों को रोकना होगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह आदेश अस्थायी रोक के तौर पर जारी किया गया है। मामले में आगे क्या होता है, यह न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरणों पर निर्भर करेगा।

अगले 73 वर्षों में धरती से मिट सकता है इंसानों का नामोनिशान?

वाशिंगटन, एजेंसी। साल 2100 तक धरती से इंसान विलुप्त हो सकते हैं। यह दावा हुआ है चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन लैंसेट की एक रिपोर्ट में। वैश्विक जोखिम के विश्लेषण से जुड़ी इस रिपोर्ट में अगली सदी तक मानव जाति के लिए सबसे बड़े खतरों को चिह्नित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस रिपोर्ट में जिन कारणों को इंसानों के लिए सबसे खतरनाक करार दिया गया है, उनमें परमाणु युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को उच्च स्तर पर रखा गया है। इसके साथ ही 17 अन्य खतरों को इंसानों की विलुप्ति के संभावित कारण के तौर पर शामिल किया गया है।

आइये जानते हैं कि जिस लैंसेट रिपोर्ट में सन 2100 तक इंसानों के विलुप्त हो जाने का डर जताया गया है, वह क्या है और उसे तैयार किसने किया है? इसमें इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा किन चीजों से बताया गया है? अलग-अलग क्षेत्रों के लिए इस



रिपोर्ट में खतरे पैदा होने की क्या वजह बताई गई है?

इंसानों की विलुप्ति का खतरा बताने वाली रिपोर्ट क्या, किसने तैयार की?

इंसानों पर विलुप्ति का खतरा बताने वाली इस रिपोर्ट को 21वीं सदी में स्वास्थ्य के लिए वैश्विक खतरों पर लैंसेट आयोग की ओर से तैयार किया गया है। यह अध्ययन प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित हुआ है।

यह रिपोर्ट क्या है?

इस रिपोर्ट में अगले 73 वर्षों (वर्ष 2100 तक) के दौरान मानव स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए 17 प्रमुख और विनाशकारी खतरों का आकलन किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एआई का गलत इस्तेमाल, जैसे- जैविक हथियार बनाना या परमाणु संघर्ष साल 2100 तक इंसानों के लिए विलुप्त होने का खतरा पैदा करते हैं।

विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यूं तो इस विलुप्ति की घटनाओं की संभावना कम है, लेकिन अगर ये होता है तो इनका प्रभाव पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होगा।

जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सहायता में कटौती, बाल कुपोषण, वायु प्रदूषण, मोटापा और महामारियों को भी प्रमुख खतरों में शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है?

इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य, विज्ञान और वैश्विक नीति से जुड़े 35 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम (आयोग) ने तैयार किया है।

वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के निदेशक और कमीशन के सह-अध्यक्ष प्रो. क्रिस्टोफर मरे इसके सह-अध्यक्ष रहे।

डॉ. नतालिया कानेम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की पूर्व कार्यकारी निदेशक और कमीशन की सह-अध्यक्ष हैं।

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) में संक्रामक रोग महामारी विज्ञान के प्रोफेसर इब्राहिम अबूबकर भी इस आयोग के प्रमुख सदस्य हैं।

इंसानों की विलुप्ति के पीछे क्या हो सकती है वजह, खतरा क्यों?

साल 2100 तक इंसानों की संभावित विलुप्ति का जोखिम उच्चतम स्तर पर पहुंचने के दो प्रमुख कारण बताए गए हैं।

होर्मुज को फिर से खोलने की कोशिश तेज

ईरान की सात शर्तों में से कुछ मानने को तैयार यूएस



तेहरान, एजेंसी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रेजाई ने सोमवार को होर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया। ईरान का कहना है कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान की सात शर्तों में से कुछ को मानने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वॉशिंगटन का जवाब नाकाफी था।

मोहसिन रेजाई ने क्या बताया?

मोहसिन रेजाई ने एक्स पर पोस्ट किया, अमेरिका ईरान की सात शर्तों में से कुछ को मानने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन हम उसके जवाब को नाकाफी मानते हैं। ईरानी कूटनीति बदल गई है और अब पुरानी स्थिति में वापसी नहीं होगी।

परिवार का मुखिया था 45 साल का हमलावर

गर्भवती की एक साल की बेटी समेत आठ लोगों को मारा

एरी (अमेरिका), एजेंसी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एरी में सामूहिक गोलीबारी में आठ लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में एक साल की बच्ची, उसकी गर्भवती मां और महिला का पांच साल का बेटा भी शामिल हैं। रविवार को बच्ची के पिता ने कहा कि हमलावर परिवार का मुखिया था। वह एक दादा भी था। वह कभी परेशान या असामान्य व्यवहार करता नहीं दिखा।

जूलियस विंडहैम ने शुक्रवार को हुई गोलीबारी के पीड़ितों की याद में बने स्मारक के पास खड़े होकर यह बात कही। उनकी एक साल की बेटी अमारियाना भी इस हमले में मारी गई। बच्ची की मां गर्भवती थी। महिला का पांच साल का बेटा और गर्भ में पल रहा बच्चा भी मारे गए। विंडहैम ने कहा, मुझे लगता है कि उसका सामान्य दिखना सिर्फ दिखावा था। वह हर दिन मुस्कुराता था और सामान्य व्यवहार करता था। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है।

45 वर्षीय हमलावर ने खुद भी अपनी जान ले ली। अधिकारियों ने उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि, एरी के पुलिस प्रमुख रिक लोराह ने बताया कि हमलावर का मारे गए आठ लोगों में से सात से पारिवारिक रिश्ता था। आठवीं मृतक महिला की दोस्त थी। पुलिस ने पीड़ितों के नाम भी सार्वजनिक नहीं किए हैं।

घर के बाहर मिलीं दो महिलाओं की लाशें- रविवार को शोक मनाने पहुंचे लोगों ने उस घर के बाहर मोमबत्तियां, फूल और खिलौने रखे, जहां शुक्रवार शाम करीब पांच



बजे से कुछ पहले हमलावर ने गोलियां चलाई थीं। विंडहैम ने ऐसी टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पर महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें थीं। उस पर लिखा था- हमेशा मेरे दिल में रहोगे। विंडहैम ने कहा, मैं इस समय किस दौर से गुजर रहा हूं, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अपने समुदाय, अपने परिवार, बेटियों, बेटों और सभी लोगों के लिए मजबूत बने रहना होगा।

पुलिस प्रमुख लोराह ने बताया कि जांचकर्ताओं को वीडियो और ऑडियो सबूत मिले हैं। इनमें घर के अंदर से धीमी आवाज में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दीं। इसके कुछ ही समय बाद दो महिलाएं वहां पहुंचीं। वे बेहद परेशान थीं और दरवाजा पीटने लगीं। इसके बाद हमलावर घर से बाहर आया। उसने दोनों महिलाओं पर गोली चलाई, जब वे उसकी ओर भाग रही थीं। फिर वह वापस घर के अंदर चला गया।

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को घर के बाहर दोनों महिलाओं के शव मिले। इसके बाद पुलिस ने ड्रोन और रोबोट की मदद ली। फिर अधिकारी घर के अंदर दाखिल हुए। पहली मंजिल पर पांच साल के लड़के और एक साल की बच्ची के शव मिले। सीढ़ियों के पास दो अन्य महिलाओं और दो युवकों के शव मिले। हमलावर दूसरी मंजिल पर मिला।

पुलिस प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीड़ितों और उनके परिवारों के सम्मान में मैं यह नहीं बताऊंगा कि घर के अंदर पुलिस अधिकारियों ने क्या देखा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा समुदाय समझे कि यह घटना कितनी गंभीर थी।



ठाणे में देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश, टीवी अभिनेत्री को बचाया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मानव तस्करी और देह व्यापार के कथित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने हिंदी धारावाहिकों और वेब सीरीज में काम कर चुकी 35 वर्षीय अभिनेत्री को सुरक्षित बचाया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके पुरुष साथी की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, गिरोह मनोरंजन जगत से जुड़ी महिलाओं को कथित तौर पर देह व्यापार में धकेलता था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आठ अक्टूबर को मीरा-भायंदर रोड स्थित एक होटल में फर्जी ग्राहक भेजकर जाल बिछाया। इसके बाद मौके पर छापा मारकर कथित महिला दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया।

● **पैसे लेते समय पकड़ी गई महिला:** पुलिस ने गिरफ्तार महिला की पहचान तबस्सुम उर्फ सोनिया उमर कुरैशी (39) के रूप में की है। आरोप है कि वह महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने के बदले पैसे ले रही थी। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

● **मनोरंजन जगत की महिलाओं को बनाते थे निशाना:** प्रारंभिक जांच के अनुसार, गिरोह कथित तौर पर टेलीविजन धारावाहिकों, वेब सीरीज और फोटोशूट में काम करने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था। पुलिस ने बचाई गई अभिनेत्री को सुरक्षा और देखभाल के लिए मुंबई स्थित रेस्क्यू फाउंडेशन में रखा है। अधिकारियों ने अभिनेत्री की पहचान और मामले से जुड़ी अन्य निजी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की हैं।

सोशल मीडिया

आमिर खान की लाडली के साथ हिरासत में बर्बरता!



आमिर खान की भांजी और एक्ट्रेस जायन मैरी खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इस वीडियो में उनके शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। जायन को 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस दौरान एक्टर इमरान खान और उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन को भी हिरासत में लिया गया था। हालांकि, कुछ घंटों बाद तीनों को छोड़ दिया गया।

क्या थी प्रदर्शन की वजह?

यह प्रदर्शन वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर किया गया था। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन में 'कॉकरोच जनता पार्टी' की मांग का समर्थन किया गया था।

जायन के वीडियो ने खींचा ध्यान: हिरासत से रिहा होने के बाद जायन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके शरीर पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, जायन को ये चोटें कब और कैसे लगीं, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने भी वीडियो में चोट लगने की वजह के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी।

लेखा वॉशिंगटन ने भी लगाए थे आरोप

इस घटना के बाद लेखा वॉशिंगटन ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव के बारे में बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि रिहाई के बाद घर जाने के लिए कैब मिलना मुश्किल हो गया था और कैब ड्राइवरों को धमकाया जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

प्रदर्शन के दौरान इमरान खान, लेखा वॉशिंगटन और जायन मैरी खान को पुलिस वैन में ले जाते हुए देखा गया था। अब जायन के वीडियो के सामने आने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

कंगना के AI वीडियो हटाने का आदेश



बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाले AI से बने डीपफेक वीडियो, फर्जी भाषण, एडिटेड तस्वीरों और अन्य आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा दी है। कोर्ट ने मेटा को आदेश में इस तरह के कंटेंट की जानकारी मिलने और आदेश की कॉपी मिलने के 72 घंटे के भीतर उसे हटाने या उसकी पहुंच बंद करने का निर्देश दिया है। संबंधित सरकारी विभागों को चिह्नित वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए जरूरी कदम उठाने को भी कहा गया है। कंगना रनौट ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उनकी पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है। इसमें AI से तैयार की गई अश्लील तस्वीरें, एडिटेड वीडियो, गलत बयान और ऐसे कंटेंट शामिल हैं जिनसे ऐसा लग सकता है कि कंगना ने कोई बात कही या कोई काम किया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ।

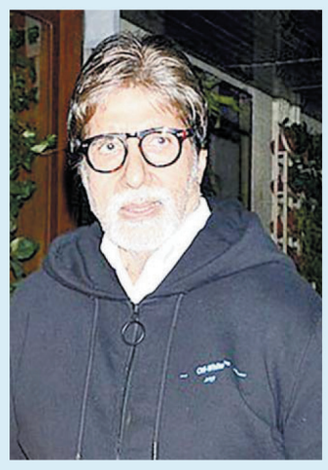
कंगना की ओर से दलील दी गई कि इस तरह के कंटेंट से उनकी प्रतिष्ठा, निजता, गरिमा और पहचान को नुकसान पहुंचता है।

8 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया था। इसके बाद 12 अक्टूबर को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए चिह्नित कंटेंट हटाने और संबंधित वेबसाइट्स तक पहुंच रोकने के निर्देश दिए।

● **72 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा:** मेटा को आदेश में चिह्नित आपत्तिजनक कंटेंट हटाने या उसकी पहुंच बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसमें वीडियो, रील्स, पोस्ट और संबंधित अकाउंट या चैनल शामिल हो सकते हैं। कंगना की पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करके बनाए गए डीपफेक, बदले हुए वीडियो-ऑडियो, फर्जी भाषण, अश्लील कंटेंट और झूठे एंडोर्समेंट पर रोक लगाई गई है।

● **कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी:** संबंधित पक्षों को कोर्ट में अनुपालन संबंधी हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। कंगना को बाद में सामने आने वाले ऐसे कंटेंट के लिंक भी संबंधित पक्षों को भेजने की अनुमति दी गई है। कंगना रनौट से पहले जान्हवी कपूर, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, सलमान खान जैसे कई सेलेब्स पर्सनैलिटी राइट्स ले चुके हैं। पर्सनैलिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व से जुड़े अधिकार। इनके तहत किसी व्यक्ति को अपने नाम, तस्वीर, आवाज, पहचान और उसकी विशिष्ट पहचान से जुड़े दूसरे पहलुओं के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मांगने का अधिकार मिल सकता है।

अमिताभ बच्चन ने फैन से हाथ मिलाने से किया इनकार



अमिताभ बच्चन ने अपने जन्मदिन के मौके पर छोटी फैन से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। दरअसल अमिताभ के 84वें जन्मदिन पर उनके मुंबई स्थित आवास 'जलसा' के बाहर फैंस की भीड़ जुटी। इस दौरान हमेशा की तरह 'संडे दर्शन' की परंपरा निभाते हुए अमिताभ बच्चन बाहर आए। तभी एक बच्ची सिक्योरिटी तोड़कर अमिताभ से हाथ मिलाने के लिए उनके करीब पहुंच गई। इस घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है। बच्ची सिक्योरिटी तोड़कर अमिताभ से हाथ मिलाने के लिए उनके करीब पहुंच गई। बच्ची सिक्योरिटी तोड़कर अमिताभ से हाथ मिलाने के लिए उनके करीब पहुंच गई।

सुरक्षा टीम से बच्ची को दूर ले जाने को कहा: वीडियो में देखा जा सकता है की जब महिला प्रशंसक अमिताभ बच्चन के करीब जाने की कोशिश करती है, तब उनके बॉडीगार्ड्स बीच में आकर उसे रोकते हैं। वह लगातार उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान अमिताभ लगातार उससे मिलने से बचते नजर आए और उन्होंने उससे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। वीडियो में एक जगह वे अपनी सुरक्षा टीम को इशारा करके उस महिला को वहां से ले जाने के लिए कहते हुए भी दिख रहे हैं।

प्राइवेट वीडियो लीक होने से टूट गईं अपूर्वा मुखीजा

एयरपोर्ट पर फूट-फूटकर रोईं 'रिबेल किड' बोलीं- माता-पिता ने भी देखा वीडियो



सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर अपूर्वा मुखीजा, जिन्हें 'रिबेल किड' के नाम से जाना जाता है, इन दिनों अपने निजी वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने को लेकर चर्चा में हैं। अपूर्वा का कथित किसिंग वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने पहली बार इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि वीडियो सामने आने की जानकारी मिलने पर वह बुरी तरह भावुक हो गई थीं और लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर खुद को संभाल नहीं पाई थीं।

अपूर्वा ने अपने यूट्यूब व्लॉग में बताया कि वायरल हो रहा वीडियो करीब एक साल पुराना है। यह एक निजी पार्टी का वीडियो था, जहां उनके साथ अमीन जैज भी मौजूद थे। अपूर्वा के मुताबिक, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोई उनके निजी पल को रिकॉर्ड कर रहा है। काफी समय बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया।

● **तुर्किये से न्यूयॉर्क जाते समय मिली जानकारी:** अपूर्वा ने बताया कि वह तुर्किये से न्यूयॉर्क जा रही थीं। इस दौरान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उनकी उड़ान में देरी हुई। इसी बीच उनके फोन पर लगातार संदेश आने लगे। लोग उनसे वायरल वीडियो के बारे में पूछ रहे थे। शुरुआत में अचानक मिले इन संदेशों से वह हैरान रह गईं, लेकिन जब उन्हें पूरे मामले का पता चला तो वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गईं।

उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन वह अपने आंसू नहीं रोक सकीं। निजी वीडियो सार्वजनिक होने और लोगों के लगातार संदेश आने से वह भावनात्मक रूप से टूट गई थीं।

● **माता-पिता को रिश्ते की नहीं थी जानकारी**

अपूर्वा के लिए इस पूरे घटनाक्रम का सबसे मुश्किल पहलू उनके माता-पिता की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता को पहले उनके रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं थी। वीडियो सामने आने के बाद उन्हें पता चला कि उनके माता-पिता ने भी इसे देख लिया है। इस बात ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी।

अपूर्वा ने अपने व्लॉग में कहा कि उनके माता-पिता को यह तक नहीं पता था कि उनका कोई प्रेमी है। ऐसे में अचानक निजी जिंदगी से जुड़ी बात सार्वजनिक हो जाने के कारण वह बेहद तनाव में आ गई थीं।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर निजी पलों की रिकॉर्डिंग और उन्हें बिना अनुमति सार्वजनिक करने को लेकर भी चर्चा हो रही है। हालांकि, वीडियो लीक होने के पीछे कौन जिम्मेदार है, इस संबंध में उपलब्ध रिपोर्ट में कोई पुष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

नाना पाटेकर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आई



नाना पाटेकर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ था। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) के एक सीनियर डॉक्टर ने रविवार को एक न्यूज एजेंसी यह जानकारी दी। डॉक्टर के मुताबिक, नाना पाटेकर को दिल का दौरा पड़ा था। हार्ट की मुख्य नस (लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी) में खून का थक्का जमने से यह स्थिति बनी। यह नस दिल के एक बड़े हिस्से तक खून पहुंचाती है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण दिल की मुख्य नस में खून का थक्का जमने से हुआ गंभीर हार्ट अटैक बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई।

नाना ने निधन से कुछ घंटे पहले दोस्त को मैसेज किया

पुलिस जांच में पता चला है कि नाना पाटेकर ने निधन से कुछ घंटे पहले अपने करीबी दोस्त अमेय नाईक से संपर्क करने की कोशिश की थी। उन्होंने 8 अक्टूबर की सुबह करीब 2:30 बजे वॉट्सऐप पर मैसेज भेजकर तबीयत ठीक नहीं होने की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने अमेय को फोन भी किया। पुलिस के मुताबिक, अमेय नाईक ने नाना पाटेकर का मैसेज सुबह करीब 3:30 बजे देखा। इसके बाद वे तुरंत उनके डोना पावला स्थित घर पहुंचे। वहां उन्होंने नाना को सोफे पर बेहोश पाया।

नवरात्रि पर नैना देवी मंदिर पहुंचीं जाह्नवी कपूर



नैनीताल में बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और रिया चक्रवर्ती अपनी नई थ्रिलर-रोमांटिक फिल्म 'पीएन 36' की शूटिंग कर रही हैं। रविवार को नवरात्रि के पहले दिन व्रत रखकर जाह्नवी कपूर होटल से करीब 150 मीटर पैदल चलकर नैना देवी मंदिर पहुंचीं। यहां उन्होंने मां की आरती की और पूजा-अर्चना की। मंदिर समिति की ओर से उन्हें मां की चुनरी भेंट की गई। जाह्नवी और रिया ने बारिश और बादलों के बीच फिल्म के एक रोमांटिक सॉन्ग की शूटिंग भी की। अब तक फिल्म की शूटिंग नैनीताल के स्विस होटल में हुई है।

शनिवार को दोनों एक्ट्रेस ने यहां शूटिंग की थी। वहीं, होटल नमः में भी फिल्म के कुछ सीन फिल्माए गए हैं। हालांकि, यह शूटिंग नैनीताल से बाहर हुई है। शूटिंग के बीच दोनों एक्ट्रेस नैनीताल में ही हैं। ब्रेक के दौरान उनके आसपास के इलाकों में घूमने की संभावना है। दोनों के कैंची धाम जाने की भी चर्चा है, हालांकि अभी दर्शन का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है।

> "रिया चक्रवर्ती के साथ नैनीताल में कर रहीं शूटिंग, बारिश के बीच रोमांटिक सॉन्ग शूट किया"

जाह्नवी कपूर अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख रही हैं। वह सुबह करीब 7 बजे मल्लीताल के रोपवे मार्ग स्थित बुल्स जिम में वर्कआउट करने पहुंची थीं। 'पीएन 36' में साउथ की एक्ट्रेस श्रीलीला और एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता भी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन उमेश बिष्ट कर रहे हैं।

धमधा और अहिवारा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने और मोदी सरकार के संरक्षण में चल रही 'वोट चोरी' के खिलाफ फूटा आक्रोश

अहिवारा में बाईक रैली , बुलेट दौड़ाते दिखे जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ। दुर्ग / धमधा - अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चलाए जा रहे ÷वोट बचाओ✓देश बचाओ÷ जनांदोलन के द्वितीय चरण (10 से 20 अक्टूबर) के तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) अंतर्गत धमधा और अहिवारा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और तानाशाह मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने आर-पार का मोर्चा खोल दिया। सैंकड़ो की संख्या में सड़कों पर उतरे आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने, उन्हें गिरफ्तार करने और पद से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग के नापाक गठजोड़ पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा सरकार के इशारे पर मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र की सरेआम बलि दे रहे हैं। धमधा में आयोजित मुख्य विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री रवींद्र चौबे एवं जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर जी की प्रतिमा को नमन कर निकाली गई विशाल पदयात्रा में कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था। एसडीएम कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाकर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग की। पूर्व कैबिनेट मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि ÷आज देश का लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली सबसे गहरे संकट में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से निरंकुश मोदी सरकार के औजार और कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। फॉर्म-6 में अवैधानिक व मनमाने बदलाव करके देश के वैधानिक मतदाताओं के अधिकार छीने जा रहे हैं और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए 'वोट चोरी' का संगठित अपराध चलाया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार को मोदी सरकार का खुला राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके दम पर वे संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट और पक्षपाती चुनाव आयुक्त को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए।÷ जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए अब जनता के फैसले पर नहीं, बल्कि ज्ञानेश कुमार जैसी कठपुतलियों की मेहरबानी पर निर्भर हो चुकी है।



चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था न रहकर भाजपा का चुनावी कार्यालय बन चुका है। हम मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार के इस लोकतंत्र विरोधी गठजोड़ को उखाड़ फेंकेंगे। जब तक इस भ्रष्ट व्यवस्था पर एफआईआर दर्ज नहीं होती और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, कांग्रेस का एक-एक सिपाही सड़कों पर डटा रहेगा।÷

अहिवारा में बाईक रैली , बुलेट दौड़ाते दिखे जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर - अहिवारा क्षेत्र में प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर खुद बुलेट चलाते हुए विशाल बाइक रैली की अगुवाई करने उतरे। वार्ड क्रमांक 01 संतोषी चौक से शुरू हुई यह आक्रोश रैली पूरे शहर में गूंजती हुई तहसील कार्यालय पहुंची, जहां भाजपाइयों और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तहसीलदार कार्यालय पहुँचकर कार्यकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 326 का पाठ किया और ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।

अहिवारा में जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा की ÷मोदी सरकार के सीधे संरक्षण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारतीय लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। लोकतंत्र को बचाने के लिए यह जंग अब जन-जन की जंग बन चुकी है। आगामी दशहरा पर्व के दौरान हम आम जनता के बीच जाकर पर्चे बांटेंगे और मोदी सरकार तथा ज्ञानेश कुमार की मिलीभगत से रची जा रही 'वोट चोरी' की घिनौनी साजिश का भंडाफोड़ करेंगे। तानाशाही का यह साम्राज्य अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा।

इस दौरान राजीव गुप्ता, शिवकुमार वर्मा, जीवन निर्मलकर, जालम पटेल, अरुण साहू, मधुसूदन राणा, धर्मेंद्र साहू, जितेंद्र वर्मा, हिम्मत ढीमर,अघनु पाल, रजत नायक ,जवाला साहू, देवेंद्र चंदेल, परमेश्वर यादव, विजय ढीमर, केबिलाल वर्मा, राज पटेल, आकाश द्विवेदी, हीरा वर्मा, उमेश साहू, संतोष बाफना, कैलाश नाहटा, जगदीश मारकंडे, धरम बर्रे, उषा सोनवानी, नागमणि साहू, ओनि महिलांग, अभिषेक जांगड़े, सुमित नारंग, आराधना, कमलेश, संतोष, भागवत बंजारे, अशोक आडिल, हेमंत साहू, योगेश, सुमन साहू, रोहित यादव, नरेश बांधे, विक्कू पटेल, बलराम पटेल, अनिल साहू, सुमंत ताम्रकर, निर्मल जैन, लूमेश्वर पटेल, पप्पू सोनवानी, कामदेव साहू , हलधर यादव, श्रवण साहू, प्रहलाद यादव, रोमन पटेल, चेतन कश्यप, नंद निर्मल, देवनाथ सोनकर, सुरेंद्र यादव, सुरेश ढीमर, ओमकुमार वर्मा, ठाकुर राम साहू, ईश्वरी निर्मल, जीवधन साहू, आशीष पांडेय, संदीप गुप्ता, अकील ख़ान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

राज्य होम्योपैथी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल से की सौजन्य भेंट



रायपुर, (जनता के गोठ)। छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय क्षेत्र के पहले होम्योपैथी महाविद्यालय में नवीन सत्र के लिए प्रवेश की अनुमति प्राप्त होने पर आज राज्य होम्योपैथी परिषद, छत्तीसगढ़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से उनके कार्यालय में सौजन्य भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि राज्य के इस पहले शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय में पठन-पाठन और प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से छत्तीसगढ़ के युवाओं को चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया अवसर मिलेगा और आम जनता को सुलभ तथा बेहतर होम्योपैथिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी।

मुलाकात के दौरान उपस्थित प्रमुख गणमान्य:

इस प्रतिनिधिमंडल में रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. जे.पी. शर्मा, रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला, तथा परिषद के सदस्यगण डॉ. मुकुंद पिंपले, डॉ. गुलाब टिकरिहा, डॉ. निर्मल भोई, डॉ. सुशील हरिरमानी, डॉ. ओंकार सिंह राजपूत, डॉ. यशपाल बावरिया, डॉ. प्रदीप चौधरी, डॉ. उत्कर्ष त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में प्रदेश के चिकित्सकगण उपस्थित रहे।

5 साल से जर्जर सड़क, खतरे में 260 विद्यार्थियों का सफर! कोटेया मार्ग के डामरीकरण के लिए अभाविप ने खोला मोर्चा

रोहित यादव / प्रतापपुर (जनता के गोठ) : शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटेया तक पहुंचने वाली सड़क की बदहाली अब विद्यार्थियों और ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। पिछले पांच वर्षों से जर्जर कोटेया-बगड़ा मार्ग के पुनः डामरीकरण की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की धरमपुर इकाई ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान में 150 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर सड़क निर्माण की मांग को समर्थन दिया।

गड्ढों में तब्दील सड़क, हर दिन जोखिम भरा सफर

जानकारी के अनुसार, कोटेया से बगड़ा तक जाने वाला यह मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहनों से आवागमन करना मुश्किल हो गया है। इस मार्ग



से करीब 260 विद्यार्थी विद्यालय पहुंचते हैं। इसके अलावा दो पंचायतों के लगभग 10 गांवों के ग्रामीण भी इसी सड़क पर निर्भर हैं। ऐसे में सड़क की बदहाली का असर विद्यार्थियों के साथ आम नागरिकों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है।

बरसात में बढ़ती परेशानी, हाथियों के विचरण से भी खतरा

धरमपुर नगर मंत्री नारायण राम पैकरा ने बताया कि बरसात के दौरान सड़क के गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह क्षेत्र हाथी प्रभावित है और हाथियों का विचरण सड़क के आसपास तथा एक ओर से दूसरी ओर होता रहता है। ऐसे में खराब सड़क के कारण विद्यार्थियों और ग्रामीणों को आवागमन में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

विद्यार्थियों की मांग—सड़क का हो जल्द डामरीकरण

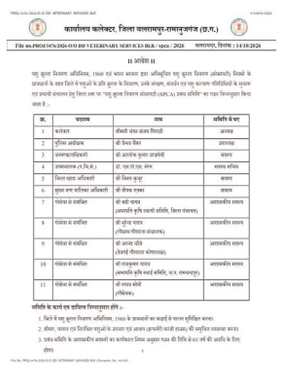
अभाविप की धरमपुर इकाई ने विद्यार्थियों के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाकर संबंधित विभाग और प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। परिषद की मांग है कि कोटेया-बगड़ा मार्ग की स्थिति का निरीक्षण कर जल्द से जल्द सड़क का पुनः डामरीकरण कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों, ग्रामीणों और राहगीरों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

अब सवाल यह है कि जब इस मार्ग से सैकड़ों विद्यार्थी और करीब 10 गांवों के लोग रोजाना गुजरते हैं, तो सड़क की बदहाली दूर करने के लिए जिम्मेदार विभाग कब ठोस कदम उठाएगा? क्या विद्यार्थियों और ग्रामीणों को राहत देने के लिए सड़क निर्माण की पहल जल्द होगी, या उन्हें इसी जर्जर मार्ग पर जोखिम उठाकर सफर करना पड़ेगा?

हस्ताक्षर अभियान में ये रहे उपस्थित

अभाविप धरमपुर इकाई के इस अभियान में नगर मंत्री नारायण राम पैकरा, श्रवण कुमार और रमाशंकर पैकरा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बलरामपुर में पशु क्रूरता पर लगेगी लगाम, SPCA समिति गठित; कलेक्टर बनीं अध्यक्ष!



बलरामपुर (जनता के गोठ) : बलरामपुर जिले में पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने, उनके संरक्षण और पशु कल्याण गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण सोसायटी (SPCA) की प्रबंध समिति का गठन किया गया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत गठित इस समिति के माध्यम से जिले में पशुओं के संरक्षण और उनके प्रति क्रूरता की रोकथाम के प्रयासों को गति देने की पहल की गई है। जारी आदेश के अनुसार, कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी को समिति का अध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वनमंडलाधिकारी आलोक कुमार वाजपेयी को सदस्य और उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. एस.पी.एस. सेंगर को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, जिला खाद्य अधिकारी विनय कुजूर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपक एक्का समिति के सदस्य होंगे।

गोसेवा से जुड़े लोगों को भी मिली जिम्मेदारी

समिति में गोसेवा और पशु कल्याण से जुड़े अशासकीय सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इनमें बद्री यादव, सुरेन्द्र यादव, आनंद चौबे, राजकुमार यादव और गौसेवक राघव सोनी शामिल हैं। इन सदस्यों की भागीदारी से पशुओं के संरक्षण और देखभाल से संबंधित गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करने में सहयोग मिलने की उम्मीद है।

बीमार और घायल पशुओं के उपचार पर रहेगा जोर

समिति की प्रमुख जिम्मेदारियों में जिले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसके साथ ही बीमार, घायल और निराश्रित पशुओं के उपचार तथा उनके लिए आश्रय की समुचित व्यवस्था करना भी समिति के दायित्वों में शामिल रहेगा। इसके लिए इन्फार्मरी और कांजी हाउस जैसी व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक पहल की जानी है।

तीन साल का होगा अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल

जारी आदेश के मुताबिक, समिति के अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल गठन की तिथि से नियमों के अनुसार तीन वर्ष निर्धारित किया गया है। समिति की समीक्षा बैठक समय-समय पर कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, ताकि पशु कल्याण से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

अब निगरानी और क्रियान्वयन पर रहेगी नजर

समिति के गठन के बाद जिले में पशु क्रूरता की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम, घायल एवं निराश्रित पशुओं को समय पर उपचार और सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। अब यह देखना अहम होगा कि समिति अपने निर्धारित दायित्वों को धरातल पर किस तरह लागू करती है और पशु कल्याण की दिशा में कितनी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होती है।

महाकुल समाज के प्रदेश अध्यक्ष के प्रयासों से महकुल जाति को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की दिशा में पहल तेज

छत्तीसगढ़ शासन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पुनः भेजा अनुशंसा संबंधी पत्र, आवश्यक कार्रवाई का किया अनुरोध

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में महाकुल समाज के हितों एवं अधिकारों को लेकर महाकुल समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री परमेश्वर यादव जी के प्रयासों से महाकुल, महकुल जाति को केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग (ह्क्ष्ट्र) सूची में शामिल कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली को पुनः पत्र प्रेषित कर पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।



दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को संयुक्त सचिव श्री अनुपम त्रिवेदी द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अवर सचिव श्री योगेश डिंगरा को पत्र भेजा गया है। पत्र में राज्य की केंद्रीय सूची में ÷महाकुल, महकुल÷ जाति के समावेशन संबंधी अनुशंसा के संबंध में पूर्व में प्रेषित पत्र की प्रति सहित प्रस्ताव को पुनः भेजा गया है, ताकि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

पत्र में विभागीय पत्र क्रमांक GEN COR/ 2065/ 2025- OBC&M, दिनांक 3 अगस्त 2026 का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि इस संबंध में आवश्यक जानकारी एवं अनुशंसा सहित प्रकरण पहले भी प्रेषित किया जा चुका है। अब शासन द्वारा पुनः पत्र भेजा जाना इस विषय पर आगे की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

महाकुल समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री परमेश्वर यादव जी के प्रयासों का उद्देश्य समाज को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा महाकुल समाज की केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किए जाने की मांग को संबंधित सरकारी एवं संवैधानिक संस्थाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। समाज को आशा है कि इस पहल से प्रकरण में आगे की आवश्यक कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा।

हालांकि, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किए जाने की अंतिम स्वीकृति अभी प्राप्त होने की पुष्टि नहीं है। वर्तमान में शासन द्वारा अनुशंसा संबंधी पत्र पुनः भेजे जाने की कार्रवाई हुई है। अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकारी की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। महाकुल समाज के लोगों ने उम्मीद जताई है कि इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग पर नियमानुसार उचित निर्णय लिया जाएगा।

रायपुर में नशे के खिलाफपुलिस की कार्रवाई, गांजा और नशीली गोलियों के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टिकरापारा थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा और नशीली गोलियां बरामद की हैं। जब्त मादक पदार्थों में 4 किलो से अधिक गांजा और 130 नाइट्रोजेपम गोलियां शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026 को भाठागांव बस स्टैंड क्षेत्र में दो अलग-अलग कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में अरसद खान (25 वर्ष), पिता अयूब खान, के कब्जे से बोरी में रखा 2 किलो 67 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत 1 लाख 3 हजार 350 रुपये बताई गई है। इसी क्षेत्र में दूसरी कार्रवाई के दौरान अकबर खान (24 वर्ष), पिता राज मोहम्मद खान, के कब्जे से पिट्ठू बैग में रखा 2 किलो गांजा बरामद किया गया। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया।

130 नशीली गोलियां भी बरामद- तीसरी कार्रवाई में पुलिस ने नवीन नाम के 17 वर्षीय किशोर के कब्जे से 130 नाइट्रोजेपम नशीली गोलियां बरामद कीं। जब्त गोलियों की कीमत 5 लाख 72 हजार 500 रुपये बताई गई है। इस मामले में भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, तीनों मामलों में गांजा और नशीली गोलियों की बरामदगी के बाद आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों के जरिए पुलिस ने क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम उठाया है।

मेंरा गांव , मेरी धरोहर ग्राम फूंडा में विराजीं मां दुर्गा के नव रूप , विशेष झांकी बनी क्षेत्र में चर्चा का विषय

दर्शन के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़।

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ। दुर्ग/ पाटन - पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत फूंडा में इस रजत वर्ष 25वा साल पर नव युवक दुर्गाउत्स्व समिति द्वारा शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर स्थापित मां दुर्गा की झांकी पूरे क्षेत्र में आकर्षण एवं आस्था का केंद्र बनी हुई है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गोत्सव समिति द्वारा भव्य दुर्गा स्थापना का आयोजन किया गया है, लेकिन इस बार की विशेष बात यह है कि पंडाल में मां दुर्गा के सभी नव रूपों (नवदुर्गा) की एक साथ नयनाभिराम और भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।

एक ही पंडाल में मां के नव रूपों का अलौकिक दर्शन- फूंडा में सजाया गया यह पूजा पंडाल अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत हो रहा है। पंडाल के विशाल मंच पर मुख्य प्रतिमा के रूप में मां दुर्गा भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके दोनों ओर देवी भगवती के नव रूपों—शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री—की अलौकिक प्रतिमाएं कतारबद्ध रूप से सजाई गई हैं। प्रतिमाओं का श्रृंगार, भव्य पृष्ठभूमि, प्रकाश व्यवस्था



(लाइटिंग) और मंच के सामने कतारबद्ध तरीके से रखे गए कलश इस झांकी की भव्यता में चार चांद लगा रहे हैं। ग्रामीण अंचल और दूर-दराज से पहुंच रहे श्रद्धालु मां दुर्गा के नव रूपों के इस एक साथ दर्शन को देखने के लिए केवल फूंडा के निवासी ही नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों से भी रोजाना श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शाम के समय आरती के दौरान पंडाल में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और पूरा माहौल भक्तिमय भजनों एवं जयकारों से गुंजायमान हो रहा है।

क्षेत्र भर में हो रही भव्य आयोजन की प्रशंसा एक ही स्थान पर नवदुर्गा के संपूर्ण दर्शन होने के कारण यह आयोजन पूरे दुर्ग और पाटन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसा अद्भुत और मनमोहक दृश्य आमतौर पर बड़े शहरों में ही देखने को मिलता है, लेकिन फूंडा की उत्सव समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सुंदर और अनुशासित व्यवस्था करके सभी का दिल जीत लिया है। आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि ग्रामीणों और युवाओं के सहयोग से यह भव्य रूप दिया जा सका है, और आगे भी धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक,संपादक-शुभम वर्मा द्वारा मकान नंबर 411, देवनगर, आदिवासी छात्रावास के सामने, शिव शंकर होटल के पीछे महादेव घाट रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित एवं छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स अनंत विहार कालोनी,दलदल सिवनी मार्ग -मोवा रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित। (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) फोन:-9300870270, 9425520408 jantakegoth@gmail.com